04 - सियासी रण में पांच राज्यः सत्ता की कुर्सी किसके नाम?

05 - देश का युवा भविष्य : शिक्षा, रोजगार और अधूरा वादा

A Daily News Magazine

भोपाल

गुरुवार, 9 अप्रैल, 2026

06 - मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः राहत की बजाए आफत बने नए नियम...

07 - संगीत, कला और साहित्य की त्रिवेणी है संकट मोचन संगीत...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 216, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

युद्ध विराम : ट्रंप को 'आंशिक जीत' पाने चुकानी पड़ी भारी क़ीमत

एंथनी जर्चर

आख़िरकार, समझदारी ने जीत हासिल की।

वॉशिंगटन समय के मुताबिक मंगलवार शाम 6 बजकर 32 मिनट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर लिखा कि अमेरिका और ईरान एक 'पक्के' शांति समझौते के काफी क़रीब पहुंच चुके हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दो हफ्तों के युद्ध विराम पर सहमति दी है।

यह बिल्कुल आख़िरी पल नहीं था, लेकिन ट्रंप की रात 8 बजे (भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह साढ़े पांच बजे) की डेडलाइन से काफी करीब था। ट्रंप के मुताबिक़ इस समय सीमा तक समझौता नहीं होता तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा और परिवहन ढांचे पर बड़े हमले करने वाला था।

यह सब इस शर्त पर निर्भर है कि ईरान भी लड़ाई रोक दे और होर्मुज़ स्ट्रेट को व्यापारिक जहाजों के लिए पूरी तरह खोल दे। ईरान ने कहा है कि वो ऐसा करेगा। लेकिन यह प्रगति मंगलवार सुबह तक बिल्कुल भी तय नहीं लग रही थी, जब ट्रंप ने ईरानी सभ्यता को 'हमेशा के लिए ख़त्म कर देने' की धमकी दी थी। इस घोषणा के साथ ट्रंप ने अपना सबसे तात्कालिक लक्ष्य हासिल कर लिया, हालांकि ईरान ने कहा है कि होर्मुज़ जलमार्ग पर उसका 'नियंत्रण' अभी भी बना हुआ है।

अब अमेरिका और ईरान अगले दो हफ्तों तक बातचीत करेंगे, जिससे स्थाई समझौते तक पहुंचने की कोशिश के लिए कुछ समय मिल गया है। यह रास्ता आसान नहीं होगा और उतार-चढ़ाव भरा रहने की संभावना है, लेकिन बाजार में इसका सकारात्मक असर दिखा।

आफ्टर-ऑवर्स ट्रेडिंग में कच्चे तेल की कीमत कई दिनों में पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स में तेज उछाल देखा गया। कुल मिलाकर, ऐसा लग रहा है कि बाजार और निवेशकों को उम्मीद है कि सबसे बुरा दौर अब पीछे छूट सकता है।

हालांकि, इतनी प्रगति भी मंगलवार सुबह तक बिल्कुल तय नहीं लग रही थी, जब ट्रंप ने कहा था कि ईरानी सभ्यता को 'हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा।' यह साफ़ नहीं है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति की इतनी चौंकाने वाली धमकी ने ईरान पर दबाव डाला और उसे उस तरह के युद्ध विराम पर सहमत किया, जिसे वह पहले ठुकरा चुका था। लेकिन यह साफ़ है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह हैरान कर देने वाला और भड़काऊ बयान (जो इसी तरह के अपशब्दों वाले एक और संदेश के सिर्फ दो दिन बाद आया) आधुनिक अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बयानों से बिल्कुल अलग है। ऐसा पहले कभी देखने या सुनने को नहीं मिला।

और अगर यह दो हफ्तों का युद्ध विराम स्थायी शांति में बदल भी जाता है, तो भी ईरान युद्ध और ट्रंप के हालिया बयान दुनिया के बाकी देशों की नज़र में अमेरिका की छवि को बुनियादी तौर पर बदल सकते हैं। एक ऐसा देश, जो कभी खुद को दुनिया में स्थिरता बनाए रखने वाली ताकत के रूप में पेश करता था, अब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की बुनियाद को हिला रहा है। एक ऐसा राष्ट्रपति, जिसने घरेलू राजनीति में परंपराओं और मानकों को तोड़ने में जैसे आनंद लिया है, अब वही काम वैश्विक मंच पर भी कर रहा है।

डेमोक्रेट नेताओं ने मंगलवार को ट्रंप के बयान की तुरंत निंदा की, और कुछ ने तो उन्हें पद से हटाने की मांग तक कर दी। कांग्रेस सदस्य जोक्विन कास्त्रो ने एक्स पर लिखा, ''यह साफ़ है कि राष्ट्रपति लगातार कमजोर हो रहे हैं और नेतृत्व करने के योग्य नहीं हैं।'' अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट्स के शीर्ष नेता चक शमर ने कहा कि जो भी रिपब्लिकन ईरान युद्ध ख़त्म करने के लिए वोट नहीं करेगा, वह 'इसके हर नतीजे की जिम्मेदारी उठाएगा।' हालांकि ट्रंप की अपनी पार्टी के कई नेताओं ने उनका साथ दिया, लेकिन यह समर्थन वैसा सर्वसम्मत नहीं था जैसा उन्हें अक्सर मिलता है।

जॉर्जिया से रिपब्लिकन सदस्य और हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के वरिष्ठ सदस्य ऑस्टिन स्कॉट ने 'सभ्यता के खत्म होने' जैसी ट्रंप की धमकी की कड़ी आलोचना की। 'राष्ट्रपति की टिप्पणियां उल्टा असर डालने वाली हैं, और मैं उनसे सहमत नहीं हूं।'

विस्कॉन्सिन के सीनेटर रॉन जॉनसन (ट्रंप समर्थक) ने कहा कि अगर ट्रंप अपनी बमबारी की योजना को लागू करते हैं, तो यह 'बहुत बड़ी गलती' होगी। टेक्सास के कांग्रेस सदस्य नेथनियल मोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो 'पूरी एक सभ्यता के विनाश' का समर्थन नहीं करते। हालांकि, व्हाइट हाउस का तर्क यह हो सकता है कि यह दबाव काम कर गया। युद्ध विराम की घोषणा करते हुए अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने अपने सभी सैन्य लक्ष्यों को 'पूरा किया और उससे भी आगे बढ़कर हासिल किया।'

ईरान की सैन्य क्षमता को काफ़ी हद तक कमजोर कर दिया गया है। हालांकि उसका इस्लामिक कट्टरपंथी शासन अभी भी सत्ता में है, लेकिन उसके कई शीर्ष नेता बमबारी हमलों में मारे जा चुके हैं। फिलहाल, अमेरिका के कई घोषित लक्ष्यों को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये उसके परमाणु हथियार कार्यक्रम की नींव है। इसके अलावा, ईरान का क्षेत्रीय सहयोगी समूहों पर अब भी प्रभाव बना हुआ है। जैसे कि यमन में सक्रिय हूती विद्रोही।

और अगर ईरान बिना किसी टोल या शुल्क की शर्त के होर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह खोल देता है तो भी इस अहम जियोपॉलिटिकल रास्ते पर उसका नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गया है। ट्रंप के युद्धविराम संदेश के बाद जारी बयान में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान अपनी 'रक्षात्मक कार्रवाई' रोक देगा और होर्मुज़ से सुरक्षित आवाजाही की अनुमति देगा, जो उसकी सशस्त्र सेनाओं के समन्वय से होगी। अमेरिका ने ईरान की 10-प्वाइंट्स योजना के 'सामान्य स्ट्रक्चर' को स्वीकार कर लिया है। इस योजना में अमेरिका से अपनी सैन्य ताकत क्षेत्र से हटाने, ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने, युद्ध के नुकसान की भरपाई करने और होर्मुज़ पर ईरान का नियंत्रण बनाए रखने जैसी शर्तें शामिल हैं।

यह कल्पना करना मुश्किल है कि डोनाल्ड ट्रंप इन सभी शर्तों को वास्तव में मान लेंगे। ये संकेत देता है कि आने वाले दो हफ्तों की बातचीत काफी कठिन और जोखिम भरी हो सकती है। फ़िलहाल के लिए, यह ट्रंप के लिए एक राजनीतिक जीत की तरह दिखता है। उन्होंने एक नाटकीय धमकी दी और मनचाहा परिणाम हासिल कर लिया। लेकिन यह युद्धविराम सिर्फ एक अस्थायी राहत है, स्थायी समाधान नहीं।

(बीबीसी हिन्दी में प्रकाशित रिपोर्ट के संपादित अंश)

थम गया महायुद्ध

'सीजफायर' का ऐलान

● न ट्रंप जीते न ईरान हारा फिर भी बन गई दोनों देशों के बीच बात ● अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते का सीजफायर,40वें दिन रुकी जंग ● ट्रम्प बोले-पाक पीएम और आर्मी चीफ की अपील के बाद फैसला

तेहरान/वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया। सीजफायर से पहले ट्रम्प ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वह उसकी पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे।

उन्होंने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की भी धमकी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन के दखल के बाद संभव हो पाई। पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के सीजफायर का प्रस्ताव रखा था, जिसे ईरान ने स्वीकार कर लिया। समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे। ईरान भी हमले बंद करेगा। इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच 10 अप्रैल को औपचारिक बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू होगी।

ईरान की दो शर्तों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी पर संकट- ईरान ने अमेरिका के साथ हुए युद्धविराम के बाद दो ऐसी मांगें रखी हैं, जिनसे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी पर सवाल खड़े हो गए हैं। पहली मांग यह है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल (शुल्क) लिया जाए। दूसरी अमरीकी सेना हटे।

ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा

ट्रम्प ने बताया कि ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा है। उन्होंने कहा कि इस पर आगे बातचीत की जा सकती है। वहीं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया है कि अमेरिका ने उसका 10 पॉइंट प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। काउंसिल के मुताबिक यह समझौता ईरान की शर्तों पर हुआ है और इसे देश की जीत बताया है। दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनी ने कहा हम सतर्क हैं।

भारत ने अमरीका और ईरान सीजफायर का स्वागत किया

भारत सरकार ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने 8 अप्रैल को जारी बयान में कहा कि यह कदम पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की दिशा में अहम साबित हो सकता है। बयान में कहा गया कि भारत पहले भी लगातार यह जोर देता रहा है कि तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति के जरिए ही इस संघर्ष को खत्म किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इस जंग से लोगों को भारी पीड़ा झेलनी पड़ी है।

युद्धविराम कर चलते बने ट्रंप, अब इजरायल चुकाएगा कीमत

तेल अवीव (एजेंसी)। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्धविराम कर जंग से बाहर निकल आए हैं जबकि सहयोगी इजरायल युद्ध के मैदान से उन्हें हैरान परेशान देख रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जीत का ढिंढोरा पीट दिया है जबकि हकीकत ये है कि ईरान ने अमेरिका की एक भी शर्त नहीं मानी। उल्टा होर्मुज स्ट्रेट पर अब तेहरान का कंट्रोल भी हो चुका है। इजरायल में सदमा है। विपक्षी नेता ने नेतन्याहू पर नाकामी के आरोप लगाए हैं। इजरायली अखबार देश की सरकार से कठिन सवाल पूछ रहे हैं। अखबारों में पूछा गया है कि क्या वाकई ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोल रहा है क्योंकि ईरान ने तो आधिकारिक बयान में जहाजों के गुजरने के लिए शर्तें लगा दी हैं। बिना ईरान सेना की इजाजत के कोई भी जहाज होर्मुज से निकल नहीं सकते।

उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिए सहज-सुगम व्यवस्था की जाए सुनिश्चित : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 9 अप्रैल से गेहूँ खरीदी आरंभ हो रही है। उन्होंने सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए सहज-सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सभी कलेक्टर्स और एसडीएम को दिए गए हैं। उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिए पेयजल और छायादार स्थान की व्यवस्था की जा रही है। गेहूँ उपार्जन जैसी महत्वपूर्ण और व्यापक गतिविधि में सामाजिक और सेवाभावी संस्थाएं भी सहयोग करें। प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह विचार किसान और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल संवाद के दौरान व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है। गेहूँ की प्रति क्विंटल कीमत को वर्तमान स्तर तक लाना बड़ी चुनौती थी, हम इसे 2700 रूपये प्रति क्विंटल तक ले जाएंगे। किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाना हमारी प्रतिबद्धता है। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसी उद्देश्य से उपार्जन केंद्रों पर गेहूँ खरीदी की बेहतर व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित किये जा रहे हैं, जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम से संपूर्ण व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाएगी। उपार्जन केंद्रों पर पंपलेट और होर्डिंग के द्वारा भी किसानों को व्यवस्था के संबंध में जानकारियां देने के निर्देश दिए गए हैं।

मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार दूसरी शादी अपराध नहीं

एमपी हाईकोर्ट ने पहली पत्नी के केस पर पति को दी राहत

जबलपुर (नप्र)। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष द्वारा मान्य शर्तों के साथ एक से अधिक पत्नी रखता है तो वह अपराध नहीं है। जस्टिस बी पी शर्मा की एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ मुस्लिम समुदाय के याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 494 के तहत दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ अन्य धाराओं के तहत दर्ज अपराध पर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।

ये है मामला

जबलपुर के मोहम्मद आरिफ अहमद जहांगीर खान की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उसकी पहली पत्नी की शिकायत पर महिला थाना में केस दर्ज है। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 498 ए , 494, 342, 323 और 506 के अपराध दर्ज करते हुए न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया था। न्यायालय के द्वारा उसके खिलाफ उक्त धाराओं के तहत चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं। जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

2002 में शिकायतकर्ता के साथ हुई थी शादी- याचिका में कहा गया था कि उसका विवाह 27 दिसंबर 2002 को शिकायतकर्ता के साथ हुआ था। पहली पत्नी ने थाने में 17 जून 2022 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि बच्चा पैदा नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता उसके साथ मारपीट करता था। याचिकाकर्ता ने 16 जून 2022 को रात करीब 10-11 बजे, जहर देकर मारने की धमकी थी। साथ ही पति ने 29 मई 2022 को दूसरी शादी कर ली और उससे आपसी सहमति से खुला यानी तलाक देने के लिए कहा।

दूसरी शादी के कारण मनगढ़ंत आरोप लगाए- याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता से उसकी शादी 20 साल पूर्व हुई थी।

शरद की सुबह

सूनी सँझा, झाँके चाँद
मुँडेर पकड़ कर आँगना
हमें, कसम से, नहीं सुहाता –
रात–रात भर जागना।

रह–रह हवा सनाका मारे
यहाँ–वहाँ से बदन उघारे
पिछवारे का पीपल जाने –
कैसे–कैसे वचन उचारे
जाने कब तक नीम पड़ेगा –
'घी मिसरी' में पागना।

कैसे मन की करूँ चिरौरी
खाली–खाली बाखर–पौरी
ऐसे मौसम तुम बाहर हो
आँगन टपके परी निबौरी
जैसे हैं अपने, वैसे हों –
दुश्मन के भी भाग ना।

हमें, कसम से, नहीं सुहाता –
रात–रात भर जागना।

– नरेश सक्सेना

कृषि, परंपरा और नवाचार के समन्वय से मप्र बना कृषि विकास का अग्रणी राज्य : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

● कृषि आजीविका का साधन ही नहीं, भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति का है मूल आधार ● राज्य सरकार खेती को लाभकारी बनाने के लिए संकल्पित भाव से बढ़ रही है आगे ● मध्यप्रदेश देश में सर्वाधिक प्राकृतिक खेती करने वाला राज्य

'समृद्ध किसान-समृद्ध मध्यप्रदेश' की थीम के साथ पूरे वर्ष प्रदेश में मनाया जा रहा है कृषि उत्सव

भोपाल/जबलपुर (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। मध्यप्रदेश में कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसायों को सह अस्तित्व की दृष्टि से बड़े सम्मान के साथ देखा गया है। समृद्ध किसान-समृद्ध मध्यप्रदेश की थीम के साथ पूरे वर्ष प्रदेश में कृषि उत्सव मनाया जा रहा है। कृषि के माध्यम से हमें प्रकृति के साथ जीने का अवसर मिलता है। देश में कृषि की परंपरा लाखों साल पुरानी है। भीम बैठिका में पुरातन काल से कृषि की परंपरा के शैलचित्र देखने को मिलते हैं। हमारे ऋषि-मुनियों ने हजारों सालों से कृषि के साथ जीने का मार्ग दिखाया है। भारतीय संस्कृति में खेती के प्रति आदर का भाव है। देश की धरती अन्न के रूप में सोना उगल रही है। देश में कभी अनाज का संकट आया था, लेकिन आज हमारे कृषि वैज्ञानिक नई-नई किस्में विकसित कर अनाज उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार खेती को लाभकारी बनाने के लिए संकल्पित भाव के साथ आगे बढ़ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की भावना के अनुरूप जय किसान, जय जवान में जय विज्ञान जोड़ा गया था, वर्तमान दौर में हम, इसमें जय अनुसंधान भी जोड़ रहे हैं। प्रदेश में किसानों को हम केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि किसानों को आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती और बेहतर मार्केट लिंकेजेस से भी सशक्त बना रहे हैं। कृषि मंथन कार्यशाला किसानों के अनुभव, विज्ञान के नवाचार, सरकार की नीतियों और बाजार की संभावनाओं को एक सूत्र में पिरोने का सशक्त प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में कृषि मंथन कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर तथा गौमाता का पूजन कर कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ किया।

इन विकास कार्यों की दी सौगातें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में 23 करोड़ 21 लाख की लागत के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण कर विकास की सौगाते दी। इनमें प्रमुख रूप से 13 करोड़ रूपये की लागत से बने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन, 1.11 करोड़ रूपये लागत के बोहानी गन्ना अनुसंधान केन्द्र के प्रशासनिक भवन, 1 करोड़ रूपये लागत के बालाघाट जिले के कृषि महाविद्यालय वारासिवनी के कौशल विकास केन्द्र के साथ ही जबलपुर में 1.26 करोड़ रूपये से बने स्वचालित तरल जैव उर्वरक उत्पादन केन्द्र का लोकार्पण किया। साथ ही किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की 4 करोड़ 92 लाख रूपये से निर्मित 4 इकाइयों का भी लोकार्पण किया गया, इसमें रीवा एवं शहडोल के ज्ञान प्रसार केन्द्र शामिल है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ गुरुवार, 9 अप्रैल 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

न ईएमआई बढ़ेगी न ही महंगे होंगे लोन

● आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव ● ब्याज दर 5.25 फीसदी पर बरकरार रखी, दी राहत

नई दिल्ली (एजेंसी)। नए वित्त वर्ष की पहली मीटिंग में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है। इसे 5.25 फीसदी पर बरकरार रखा है। इससे लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई नहीं बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 8 अप्रैल को मॉनीटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों की जानकारी दी। इससे पहले फरवरी में भी रेपो रेट में बदलाव नहीं हुआ था। आरबीआई ने आखिरी बार दिसंबर 2025 में ब्याज दर 0.25 घटाकर 5.25 फीसदी की थी। आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक इस फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। आरबीआई गवर्नर

के मुताबिक, महंगाई में उछाल का खतरा अभी टला नहीं है। खराब मौसम और बेमौसम बारिश से फल, सब्जियों और अनाज की कीमतें बढ़ने की आशंका है। ईरान-इजरायल जंग से सप्लाई चैन पर असर पड़ रहा है। आरबीआई अभी रुको और देखो की नीति अपना रहा है। ग्लोबल मार्केट में मची उथल-पुथल को देखते हुए आरबीआई जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता। बैंक अभी दुनिया भर के आर्थिक हालातों पर नजर रखना चाहता है। इसी वजह से ब्याज दर में बदलाव नहीं किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 आरबीआई के होते हैं, जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आरबीआई की मीटिंग हर दो महीने में होती है।

मणिपुर में हिंसा की ताजा घटना के बाद शांति

● अधिकारियों ने कहा-तनाव है लेकिन माहौल ठीक रहा

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर में हुई हिंसा की ताजा घटना पर अधिकारियों ने बुधवार को ताजा अपडेट दिए। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बिष्णुपुर में हुए बम हमले में दो बच्चों की मौत के बाद मणिपुर के पांच घाटी जिलों में बुधवार को स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि इलाके में कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाओं पर रोक और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके। बता दें कि राज्य के बिष्णुपुर में एक दिन पहले हुए बम हमले के बाद हिंसा भड़क गई थी। इस संबंध में अधिकारी ने बताया कि

हिंसा के बाद से ही इंफाल ईस्ट और वेस्ट, बिष्णुपुर, थौबल और काकचिंग जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई जो अब तक जारी है। पुलिस के अनुसार, मंगलवार को तड़के मोइरांग ट्रोंग्लाओबी में संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा फेंका गया बम एक घर पर गिरा, जिससे घर में सो रहे पांच वर्षीय लड़के और छह महीने की बच्ची की मौत हो गई तथा उनकी मां घायल हो गईं। अधिकारी ने कहा, रात भर की झड़पों के बाद स्थिति नियंत्रण में है। आज सुबह किसी भी प्रकार की हिंसा की सूचना नहीं मिली है। कुल मिलाकर स्थिति शांत है। उन्होंने बताया कि मंगलवार देर रात इंफाल ईस्ट और वेस्ट जिलों के कुछ स्थानों पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं जिसके बाद पुलिस कर्मियों को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। प्रदर्शनकारियों ने इंफाल पूर्वी जिले के खुरई लामलॉन्ग और वांगखेई में टायर जलाए और कार्रवाई की मांग की।

कोर्ट धार्मिक परंपरा को अंधविश्वास नहीं कह सकता

● सरकार बोली-आप एक्सपर्ट नहीं, यह फैसला विधायिका करेगी ● कोर्ट बोला- हमें रिव्यू का पूरा अधिकार, भेदभाव का है मामला

नई दिल्ली (एजेंसी)। धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ भेदभाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दूसरे दिन की सुनवाई जारी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- कोई सेक्युलर अदालत किसी धार्मिक प्रथा को सिर्फ अंधविश्वास नहीं कह सकती, क्योंकि उसके पास ऐसा तय करने की विशेषज्ञता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो चीज नगालैंड के किसी समुदाय के लिए धार्मिक हो सकती है, वही मेरे लिए अंधविश्वास लग सकती है। हमारा समाज बहुत विविधतापूर्ण है, यहां अलग-अलग लोग, धर्म और मान्यताएं हैं। ऐसे में अदालत के लिए ऐसा फैसला देना खतरनाक हो सकता है। इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा मिस्टर मेहता, आपने बात को बहुत आसान बना दिया है। अदालत के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है कि वह यह तय कर सके कि अंधविश्वास क्या है।

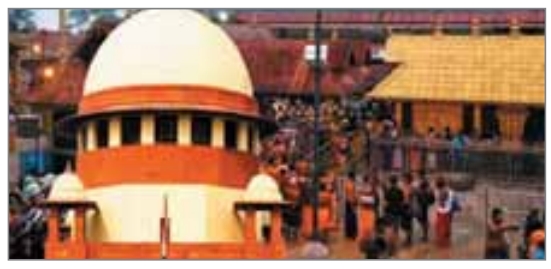

उसके बाद उस पर कानून बनाना या कार्रवाई करना विधानमंडल (संसद-विधानसभा) का काम हो सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अंतिम फैसला सिर्फ विधानमंडल ही करेगा। धर्म के मामलों में तर्क उसी तरह लागू नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा रिव्यू पिटीशन

धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला बीते 26 सालों से देश की अदालतों में हैं। 2018 में, 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी थी। इसके बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं।

सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान बेंच 7 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 50 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट में रिव्यू पिटीशनरों और उन्हें सपोर्ट करने वाले 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक, जबकि विरोध करने वाले 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक दलीलें दे सकेंगे। सीजेआई- भले ही आप सांस्कृतिक या सामाजिक मानदंडों को नजरअंदाज कर दें, लेकिन इस प्रावधान की जांच करते समय इन सिद्धांतों को आधार न बनाएं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बात महिलाओं के लिए अपराध हो और पुरुषों के लिए अपराध न हो। मेहता- मुझे इस फैसले से तीन आपत्तियां हैं।

किसानों के कल्याण, समृद्धि और खुशहाली के लिए

राज्य सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं महत्वपूर्ण निर्णयः कृषि मंत्री

पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ खेती के लिए नरवाई प्रबंधन को किया जा रहा है मजबूत

भोपाल (नप्र)। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों के कल्याण समृद्धि और खुशहाली के लिए अनेक प्रयास किया जा रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ यादव द्वारा किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। इस वर्ष गेहूं उपार्जन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा घोषित 40 रुपये का अतिरिक्त बोनस सहित किसानों को 2625 रूपये प्रति किंवटल की राशि मिलेगी। कृषि मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ खेती के लिए नरवाई प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश में धारा 163 के तहत नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत ढाई हजार रुपए से लेकर 15 हजार हजार रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पराली प्रबंधन यंत्रों जैसे हैप्पी सीडर और सुपर सीडर पर

अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। किसानों को विभिन्न माध्यमों से पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026 में सरसों उत्पादक किसानों के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू की है। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5950 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे प्रदान की जायेगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 में किसानों के लिए उड़द की सरकारी खरीद पर 600 रुपके प्रति क्विंटल का बोनस देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्प 7800 रुपये प्रति किंवटल है जिसमें 600 रूपये अतिरिक्त बोनस सहित किसानों को 8400 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा।

मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा लगभग 55 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है।

मुरैना में रेत माफिया का दुस्साहस

● फॉरेस्ट कॉन्स्टेबल हरिकेश गुर्जर को ट्रैक्टर से कुचला, मौत

मुरैना (नप्र)। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में रेत माफियाओं का दुस्साहस बढ़ते जा रहा है। आए दिन सरकारी अधिकारियों पर हमले की खबर आते रहती है। अब मुरैना में रेत माफिया ने दुस्साहस दिखाते हुए एक फॉरेस्ट कॉन्सेटबल को ट्रैक्टर से कुचल दिया है। अस्पातल लाने पर कॉन्स्टेबल हरिकेश गुर्जर की मौत हो गई है।

इस मामले में मुरैना के एडिशनल एसपी सुरेंद्र पाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रानपुर तिराहे पर फॉरेस्ट विभाग द्वारा कार्रवाई करते समय ट्रैक्टर चालक ने फॉरेस्ट के आरक्षक हरिकेश गुर्जर को कुचल दिया। जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपियों को आईडेंटिफाई कर लिया गया है जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल मृतक आरक्षक के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है।

● कार्रवाई के लिए पहुंची थी टीम- दरअसल, रानपुर तिराहे पर फॉरेस्ट की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। साथ ही रेत से भरे एक ट्रैक्टर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी रेत से भरे ट्रैक्टर के चालक ने फॉरेस्ट विभाग के आरक्षक हरिकेश गुर्जर को ट्रैक्टर कुचल दिया। हरिकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके साथी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है।

बुधवार की सुबह कॉन्स्टेबल को रौंदा

दरअसल, चंबल नदी में सख्ती के बावजूद अवैध रेत उत्खनन जारी है। कई बार प्रशासन की मिलीभगत भी सामने आती है। वहीं, जब प्रशासन के अधिकारी रोकने की कोशिश करते हैं तो रेत माफिया उनकी जान लेने से भी बाज नहीं आते हैं। बुधवार की सुबह मुरैना जिले के दिमनी इलाके स्थित रानपुर तिराहे पर रेत माफिया ने फॉरेस्ट कॉन्स्टेबल को कुचल दिया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन

● राहुल गांधी-मल्लिकार्जुन खरगे ने जताया शोक

नई दिल्ली (एजेंसी)। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मेरठ से तीन बार सांसद रहीं मोहसिना किदवई का बुधवार को निधन हो गया। 93 साल की उम्र में किदवई ने सुबह चार बजे अस्पताल में आखिरी सांस ली। नोएडा के सेक्टर 40 स्थित आवास से मोहसिना किदवई की अंतिम यात्रा दोपहर 3 बजे निकलेगी। मोहसिन किदवई के निधन पर कई राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है,पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद मोहसिना किदवई जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। वे कांग्रेस पार्टी की एक वरिष्ठ और निष्ठावान नेता थीं, जिनका संपूर्ण जीवन जनसेवा का उदाहरण रहा है। अपनी सादगी, सौम्यता और गरिमामय राजनीतिक सफलता से उन्होंने देश की कई पीढ़ियों की महिलाओं को प्रेरित किया। दुख की इस घड़ी में, मैं उनके परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

टीएमसी का आरोप, चुनाव आयोग ने 5 मिनट में भगाया

● एसआईआर पर आपत्ति जताने गए थे, सीईसी ने कहा-यहां से हट जाओ

सीईसी ने कहा-इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव भय मुक्त होंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और चुनाव आयोग आमने-सामने आ गए हैं। सांसद डेरेक ओ'ब्रायन के नेतृत्व में टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल बुधवार सुबह दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। डेरेक ने कहा कि हमने एसआईआर के मुद्दे पर समय मांगा था, लेकिन मीटिंग के दौरान हमारे साथ खराब व्यवहार किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने हमें सिर्फ 5 मिनट में भगा दिया। डेरेक ओ'ब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैठक सुबह 10.02 बजे शुरू हुई और 10.07 बजे खत्म हो गई। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, डेरेक ओ ब्रायन ने सीईसी को बोलने से रोका और धमकी दी। वह कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। ईसी ने कहा-बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित और हिंसा रहित होंगे।

चिल्लाने लगे डेरेक ब्रायन नाराज सीईसी ने भगाया

चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने डेरेक ओ 'ब्रायन से बैठक में शालीनता बनाए रखने को कहा था। लेकिन डेरेक आयोग के परिसर में चिल्लाने लगे और अनुचित व्यवहार करने लगे। प्रतिनिधिमंडल में डेरेक ओ ब्रायन के अलावा साकेत गोखले, मेनका गुरुस्वामी और सागरिका घोष शामिल थीं। बंगाल में 91 लाख वोटरों के नाम हटे :पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 91 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। अक्टूबर 2025 में कुल वोटर 7.66 करोड़ थे। इनमें से अब तक 90.83 लाख नाम हटाए गए। लगभग 11.85 फीसदी वोटर कम हो गए। यानी अब राज्य में 6.76 करोड़ वोटर हैं। चुनाव आयोग अब फाइनल आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इसके अलावा 27.16 लाख के नाम हटाए गए।

दीवाली से पहले एमपी में यूसीसी लागू करने की तैयारी

● सीएम ने कैबिनेट बैठक में दिए संकेत

भोपाल (एजेंसी)। डॉ. मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारी कर रही है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों से कहा कि यूसीसी का अध्ययन करें, इसे राज्य में लागू करना है। इस संकेत के बाद गृह विभाग में प्रक्रिया तेज हो गई है, क्योंकि यूसीसी बिल तैयार करने की जिम्मेदारी इसी विभाग की है। सूत्रों के अनुसार, जल्द ही राज्य स्तर पर एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। इसी साल दीवाली से पहले प्रदेश में यूसीसी लागू किया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने से पहले गोवा और उत्तराखंड में कुछ समय पहले लागू किए गए यूसीसी का अध्ययन किया जा रहा है। जिससे मध्य प्रदेश के लिए व्यावहारिक और संतुलित मॉडल तैयार किया जा सके।

होर्मुज में फंसे 16 जहाजों को लाने की तैयारी हो गई शुरू

सीजफायर के तुरंत बाद भारत ने ईरान से साध लिया संपर्क

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम एशिया में ईरान-अमेरिका के बीच घोषित सीजफायर की घोषणा के तुरंत बाद बुधवार को भारत ने ईरान से संपर्क साधा है ताकि होर्मुज के पश्चिम में उसके जो तेल व गैस के जहाज फंसे हैं उन्हें तुरंत वहां से स्वदेश लाया जा सके। भारत सरकार ने सीजफायर का स्वागत करते हुए आशा जताई है कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति कायम होगी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है, हम घोषित युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की ओर ले जाएगा। जैसा कि हम पहले से लगातार वकालत कर रहे थे, संघर्ष को कम करने के साथ संवाद और कूटनीति ही चल रहे संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए आवश्यक हैं। भारत ने आगे कहा है कि संघर्ष से पहले ही लोगों को अपार पीड़ा पहुंची है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क बाधित हुए हैं। भारत उम्मीद करता है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की निर्बाध स्वतंत्रता बनी रहेगी और वैश्विक वाणिज्य का सामान्य प्रवाह बहाल होगा।

भारत के 16 जहाज पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए हैं

वर्तमान में भारत के 16 जहाज होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए हैं। इनमें अधिकांश तेल और गैस से जुड़े जहाज हैं। इन जहाजों में तकरीबन दो लाख टन से ज्यादा एलपीजी है जिसकी भारत को सख्त जरूरत है। इन जहाजों को तुरंत निकालने के लिए भारतीय सरकार ईरान के साथ लगातार संपर्क में है। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है, जिसमें पश्चिम एशिया से आने वाला हिस्सा करीब 60 प्रतिशत है। होर्मुज जलडमरूमध्य में कोई भी अस्थिरता भारत की ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए गंभीर खतरा बन जाती है।

अब राजस्थान की रिफाइनरी से नहीं निकलेगा कचरा, सबसे आधुनिक भी

● पीएम 21 अप्रैल को करेंगे इसका उद्घाटन, 79 हजार करोड़ में बनी

जयपुर (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा जिले में पचपदरा रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के लिए रिफाइनरी के अलग मायने हैं। प्रोजेक्ट से बाड़मेर-जैसलमेर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स व सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। जनवरी से ही रिफाइनरी के पहले चरण के ट्रायल रन (कच्चे तेल का प्रसंस्करण) की तैयारी शुरू कर दी गई थी। इसमें जल्द कमर्शियल उत्पादन शुरू हो जाएगा। मोदी 2 महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। पचपदरा रिफाइनरी का शिलान्यास पहली बार 22 सितंबर 2013 को हुआ था। उस समय सोनिया गांधी ने रिफाइनरी का शिलान्यास किया था।

नरोत्तम मिश्रा करेंगे 'कम बैक'

हेमंत खंडेलवाल के साथ बंद कमरे में हुई मीटिंग, कांग्रेस खेमे में बढ़ रही टेंशन

भोपाल (नप्र)। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना है। वर्तमान कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती अयोग्य घोषित हो गए हैं। उन्हें बैंक धोखाधड़ी के केस में तीन साल की सजा हुई है। इसके बाद पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता बढ़ गई है। वह चुनाव में हार के बाद मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर हैं। मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात हुई है।

दरअसल, 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा महज 7,742 वोटों से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने उन्हें चुनाव हराया था। भारती को सजा होने के बाद बीजेपी दतिया विधानसभा सीट से उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं, कांग्रेस अयोग्यता को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है। अगर वहां से राहत नहीं मिली तो बीजेपी की राहें थोड़ी आसान हो सकती है।

खंडेलवाल और मिश्रा में हुई मुलाकात- वहीं, हाईकोर्ट से अगर फैसला नहीं पलटता है तो दतिया में छह महीने के अंदर उपचुनाव करवाना अनिवार्य होगा। ऐसे में तैयारियां शुरू हो गई। नरोत्तम

मिश्रा की सक्रियता फिर से बढ़ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ उनकी बंद कमरे में मुलाकात हुई है। अटकलें हैं कि संभावित उपचुनाव को लेकर ही दोनों के बीच चर्चा हुई होगी।

विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति गड़बड़- विधायकों के कानूनी पचड़े में उलझने की वजह कांग्रेस की स्थिति विधानसभा में गड़बड़ हो गई है। अभी कांग्रेस के 63 विधायक थे। विजयपुर विधानसभा से विधायक मुकेश मल्होत्रा विधायक तो हैं लेकिन उन्हें राज्यसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। दतिया से राजेंद्र भारती अयोग्य ठहरा दिए गए। ऐसे में कांग्रेस विधायकों की संख्या 61 बच गई। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस 58 वोटों की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस के साथ क्रॉस वोटिंग की भी संभावना है। ऐसी आशंका नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जता चुके हैं।

नरोत्तम मिश्रा के लिए नई उम्मीद

कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। वहीं, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए एमपी के बदलते सियासी समीकरण एक नई उम्मीद की किरण हैं। अगर उपचुनाव की संभावना बनती है तो वह दतिया सीट से फिर दावेदार हो सकते हैं। दूसरी तरफ यह भी अटकलें हैं कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती हैं। हालांकि उनके चुनाव हारने के बाद कई तरह की अटकलें सामने आती रहैं। इससे पहले भी वह राज्यसभा की रेस में शामिल थे। फिर प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आए। लेकिन बात चर्चाओं से आगे नहीं बढ़ पाई। अब फिर से उनके लिए नई संभावना है। इसे देखते हुए सक्रियता बढ़ गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा कांग्रेस को इस बात पर आत्ममंथन करना चाहिए कि उसके चुने हुए नेता या उम्मीदवार आपराधिक मामलों में क्यों फंस रहे हैं। हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में बदले सियासी हालात की वजह से कांग्रेस को नुकसान की अटकलें हैं। वहीं, बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर उपचुनाव होता है तो दतिया सीट पर कब्जा करने का मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव की राह आसान हो सकती है।

छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एबीवीपी का उग्र प्रदर्शन

- **भोपाल में रोड जाम, शराब दुकान पर पथराव; पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई**

भोपाल (नप्र)। कॉलेज के पास संचालित शराब दुकान के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने उग्र प्रदर्शन किया। एमएलबी गर्ल्स कॉलेज और एसवी को-एड कॉलेज के नजदीक शराब दुकान होने से नाराज छात्रों ने सड़क जाम कर दी और दुकान पर पथराव भी किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। एबीवीपी ने प्रशासन पर नियमों की अनदेखी और छात्राओं की सुरक्षा से समझौता करने के आरोप लगाए, जबकि प्रशासन ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है।

छात्राओं की सुरक्षा पर उठे सवाल, सड़क जाम कर किया विरोध- भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बुधवार दोपहर जोरदार प्रदर्शन किया। राजा भोज सेतू से पॉलिटेक्नीक चौराहा तक का रास्ता जाम कर दिया गया, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन प्रदर्शन धीरे-धीरे उग्र होता गया।

शराब दुकान पर पथराव, बोर्ड फाड़ा- प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने शराब दुकान के बोर्ड पर चढ़कर उसे फाड़ दिया। इतना ही नहीं, दुकान पर पथराव भी किया गया और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस दौरान ट्रैफिक खुलवाने में लगे प्रशासनिक अमले और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई।

100 मीटर दायरे में शराब दुकान, नियमों पर सवाल- एबीवीपी की केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य शालनी वर्मा ने आरोप लगाया कि पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित शराब दुकान, एमएलबी गर्ल्स कॉलेज और एसवी को-एड कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि यह नियमों का सीधा उल्लंघन है और इसमें प्रशासन की मिलीभगत साफ नजर आती है।

मोनालिसा की उम्र को लेकर एनएचआरसी ने लिया संज्ञान

- **एसपी को दिए सख्त निर्देश, सात दिनों में मांगी रिपोर्ट**

खरगोन (नप्र)। 'वायरल गर्ल' मोनालिसा और फरमान के विवाह विवाद ने अब राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींच लिया है। अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए संज्ञान लिया है और पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उधर पुलिस अधीक्षक ने जांच कर प्रतिवेदन भेजने की बात कही है।

आयोग ने जारी किया नोटिस- आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, आयोग के समक्ष 27 मार्च 2026 को प्राप्त शिकायत में आरोप लगाया गया कि महेश्वर की एक किशोरी, जो महाकुंभ मेले के दौरान रुद्राक्ष बेचने के वीडियो से सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उसने अपनी उम्र लगभग 16 वर्ष बताई थी। इसके बावजूद

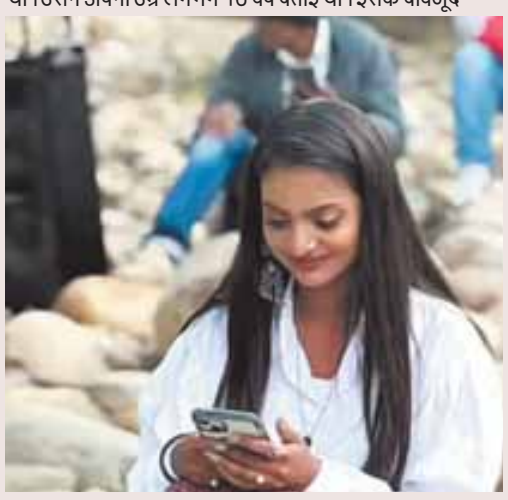

उसका विवाह केरल में कर दिया गया जो कि कानूनन गंभीर मामला हो सकता है।

उम्र से संबंधित दस्तावेजों में हेरफेर- शिकायत में यह भी आशंका जताई गई है कि लड़की की उम्र से संबंधित दस्तावेजों में हेरफेर या गलत जानकारी दी गई हो सकती है। साथ ही विवाह में दबाव, धोखाधड़ी या पहचान छिपाने जैसे पहलुओं की भी जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दस्तावेजों के सत्यापन और विवाह की सहमति की स्थिति स्पष्ट करने की अपील की है।

आयोग ने मानवाधिकारों का उल्लंघन माना- आयोग ने प्रथम दृष्टया इस मामले को मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन से जुड़ा माना है। इसके तहत एनएचआरसी की बेंच ने खरगोन के एसपी को निर्देश दिया है कि वे मामले की विस्तृत जांच कर 7 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जांच के दिए निर्देश

इसके अलावा आयोग ने मध्यप्रदेश और केरल के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों को आपसी समन्वय के साथ जांच करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मामले के सभी पहलुओं की सही और निष्पक्ष पड़ताल हो सके। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि जांच में लड़की के नाबालिग होने की पुष्टि होती है, तो पोक्सो एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही पीड़िता की सुरक्षा, काउंसलिंग और पुनर्वास के लिए भी आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।

इस बारे में खरगोन एसपी रवींद्र वर्मा ने कहा कि नोटिस प्राप्त हुआ है, और जांच के आधार पर जो भी तथ्य पाये जाएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई कर प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा।

भोपाल में टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन

डीपीआई का घेराव करने पहुंचे टीचर्स; कहा- पुराने नियमों पर नई शर्त गलत

भोपाल (नप्र)। भोपाल में टीईटी अनिवार्यता के आदेश के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन शुरू कर दिया है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा का गठन करते हुए बुधवार को लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेशभर में कलेक्ट्रेट कार्यलय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं।

शिक्षकों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के नाम पर जारी आदेश से हजारों पुराने शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। संगठनों ने सरकार से टीईटी आदेश निरस्त करने और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग उठाई है।

अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के सदस्य उपेंद्र कौशल ने बताया कि भोपाल में विभिन्न शिक्षक संगठनों के जिलाध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संयुक्त मोर्चा शाखा का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 8 अप्रैल को राजधानी में जिलास्तरीय प्रदर्शन कर लोक शिक्षण संचालनालय मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा जाएगा।

वहीं, राजधानी भोपाल में शाम 4 बजे मोर्चा के बेनर तले सैकड़ों शिक्षक डीपीआई मुख्यालय भोपाल पर एकत्र होकर टीईटी परीक्षा आदेश का विरोध कर रहे हैं। अपनी मांगों संबंधी ज्ञापन आयुक्त लोक शिक्षण को सौंपेंगे।

मोर्चा के राजेश साहू, मोहन शर्मा, निलेश आर्य, शीबा खान, रागिनी सैनी, कविता तिवारी, गिरीश द्विवेदी, राकेश पाण्डेय, दर्शन ओढ़, भंवरलाल, राकेश पटेल, इत्यादि ने समस्त शिक्षकों से अधिक से अधिक संख्या में डीपीआई मुख्यालय पर ज्ञापन प्रदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की है।

ऑस्ट्रेलियाई संसद में धीरेंद्र शास्त्री ने कराया हनुमान चालीसा पाठ

बोले- युद्ध लड़े जाएं, लेकिन गोली-बारूद से नहीं, बल्कि गरीबी से

खजुराहो (नप्र)। मध्यप्रदेश में छतरपुर जिले के बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 8 से 15 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। यहां पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी वहां की संसद में हनुमान चालीसा पाठ किया गया। थोड़ी देर में विश्व-शांति और भारतीय संस्कृति विषय पर संबोधित किया। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अमेरिका-इजराइल और ईरान के युद्ध पर कहा कि इससे खतरनाक युद्ध तो भारत में महाभारत का हुआ था, लेकिन जिस जमीन के लिए महाभारत हुई, वह जमीन आज भी मौजूद है, लेकिन जो लड़े वह निपट गए। युद्ध कोई रास्ता नहीं है।

एक कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्राध्यक्ष सुन लें कि शांति को पाने का एक ही रास्ता है कि संतुष्ट हो जाएं। उन्होंने कहा कि युद्ध जरूर लड़े जाएं, लेकिन मिसाइल, गोला-बारूद से नहीं, बल्कि गरीबी से लड़ना चाहिए। इसमें प्रतियोगिता होना चाहिए कि कौन सा देश सबसे पहले अपने यहां से गरीबी दूर करता है। कार्यक्रम में पहले पहले भारतीय मूल की युवतियों ने भारतीय नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद कलाकार ने एकल नृत्य प्रस्तुत किया। इससे पहले, बुधवार सुबह वे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के एयरपोर्ट पर उतरे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री एयरपोर्ट पर पहुंचे, भक्तों ने जय-जय श्रीराम के नारे लगाए। वहां रहने वाले भक्तों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया।

इसमें ऑस्ट्रेलियाई संसद से जुड़े प्रतिनिधि, इंडो-ऑस्ट्रेलियाई समाज के गणमान्य अतिथि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। संबोधन के आखिर में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने मौजूद लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया।

मप्र में 3 चक्रवात एक्टिव, रायसेन, भोपाल उज्जैन में हुई बारिश

11 जिलों में अलर्ट, दतिया, निवाड़ी, छतरपुर और टीकमगढ़ में ओले गिरने का अनुमान

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) एक्टिव है। इस वजह से आंधी-बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। बुधवार को भोपाल, शिवपुरी, उज्जैन, रतलाम, इटारसी, छतरपुर और रायसेन में हलकी तो कहीं तेज बारिश हुई। मौसम केंद्र भोपाल ने ग्वालियर, भिंड, मुरैना, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर समेत 18 जिलों में बारिश होने का अलर्ट है, वहीं दतिया, निवाड़ी, छतरपुर और टीकमगढ़ में ओले गिरने का अनुमान जताया है। इससे पहले मंगलवार को भिंड, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, गुना, अशोक नगर, टीकमगढ़, सतना के चित्रकूट और रीवा में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहा। कहीं, तेज आंधी चली तो कहीं बारिश का दौर जारी रहा। शिवपुरी, दतिया, धार, पीथमपुर और झाबुआ में तेज बारिश हुई। वहीं रतलाम में धूल भरी हवाएं चलीं।

10वीं-12वीं अब फेल-पास सबको मिलेगा दूसरा मौका

भोपाल (नप्र)। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल ने इस साल से छात्रों के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब पारंपरिक पूरक परीक्षा प्रणाली को खत्म कर 'द्वितीय परीक्षा' शुरू की जा रही है, जिसमें फेल और पास दोनों तरह के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। खास बात यह है कि छात्र अब सिर्फ फेल विषयों के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतर अंक लाने के लिए भी किसी विषय में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। यह परीक्षा 7 मई 2026 से शुरू होगी। बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों को अपने रिजल्ट सुधारने का बेहतर अवसर मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने पूरक परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। पहले हाईस्कूल में अधिकतम दो विषय और हायर सेकेंडरी में एक विषय में फेल छात्र ही पूरक परीक्षा दे सकते थे। लेकिन अब 'द्वितीय परीक्षा' के तहत सभी छात्रों को समान अवसर मिलेगा।

फेल के साथ पास छात्र भी दे सकेंगे परीक्षा- नई व्यवस्था के अनुसार, जो छात्र किसी विषय में अनुत्तीर्ण हैं, उनके लिए उस विषय की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। वहीं, जो छात्र पास हैं, वे भी अपने अंक सुधारने के लिए स्वेच्छा से किसी भी विषय में शामिल हो सकते हैं। यह बदलाव छात्रों के लिए बड़ा राहत भरा कदम माना जा रहा है। बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, हायर सेकेंडरी (12वीं) की द्वितीय परीक्षा 7 मई से 25 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी। वहीं हाईस्कूल (10वीं) की परीक्षा 7 मई से 19 मई 2026 के बीच होगी। सभी परीक्षाएं निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होंगी।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती शमी ने की पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता की समीक्षा

भोपाल (नप्र)। अपर मुख्य सचिव खाद्य श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, नगर निगम एवं नगर पालिका के अधिकारी तथा ऑयल कंपनी एवं सीजीडी के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि ऐसे हाउसहोल्ड जहां पीएनजी की लाईन कनेक्ट की जा चुकी है, उनको आगामी 10 दिवस के अंदर पीएनजी सप्लाई शुरू करें। ऐसे उपभोक्ताओं को समझाईश भी दी जाये कि यदि उनके द्वारा पीएनजी सप्लाई नहीं ली जाती है, तो भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 03 माह में उनकी एलपीजी सप्लाई बंद की जा सकती है। एसीएस श्रीमती शमी ने गृह विभाग के अधीन आने वाले संस्थाओं/ सुधार गृहों के साथ-साथ पुलिस, सीएपीएफ, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, ऑफिसर्स कॉलोनी, सामान्य प्रशासन पूल के घरों, पुलिस मुख्यालय, पुलिस कॉलोनी, आदि में जहां से आस-पास पाईपलाईन बिछी हुई है, उनको प्राथमिकता के आधार पर पीएनजी कनेक्शन देने के निर्देश दिये।

बैठक में बताया गया कि ऐसे क्षेत्र जहां पाईपलाईन बिछी हुई है, उनके रहवासियों एवं व्यवसायियों की सूची तैयार की जाकर कॉलोनियों में कैम्प लगाने की कार्यवाहीं की जा रही है। जिलों को निर्देश दिये गये कि प्रचार-प्रसार एवं कैम्प लगाने की कार्यवाहीं में स्थानीय निकाय नगर निगम एवं नगर पालिका के अधिकारियों तथा वार्ड पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाये।

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में जहां आस-पास पाईपलाईन गई है, उन क्षेत्रों की औद्योगिक इकाईयों की पहचान की जाकर पीएनजी पर शिफ्ट करने के निर्देश दिये गये। सीजीडी संस्थाओं के मैन पावर में वृद्धि करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पॉलीटेक्निक आई.टी.आई. एवं अन्य संस्थाओं से प्रशिक्षार्थियों की सूची प्राप्त कर सीजीडी संस्था को उपलब्ध करायी जा रही है, जो उन्हें लघु प्रशिक्षण देने के बाद कार्य में लगायेंगे।

ऑयल कंपनी से प्राप्त जानकारी के आधार पर, जिले के माईग्रेट लेबर तथा छात्रों को खाना पकाने के लिए गैस उपलब्ध कराने के लिए ऑयल कंपनी द्वारा 5 केजी के सिलेण्डर 1529 रूपये प्रति कनेक्शन के मान से उपलब्ध कराये जा रहे हैं। ऐसे सिलेण्डर बगैर एड्रेस प्रूफ के प्राप्त किये जा सकते हैं। ऐसे 5 केजी सिलेण्डर को रिफिल कराने के लिए रिफिल चार्ज 585 रूपये है। नगर निगम/नगर पालिका द्वारा जिंगल के माध्यम से कचरा गाड़ी के द्वारा पीएनजी का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे हर घर को पीएनजी के लाभ एवं पीएनजी कनेक्शन लगाने की प्रक्रिया से अवगत कराया जा सकता है।

प्रदेश में 9 से 23 अप्रैल तक मनाया जाएगा 8वां पोषण पखवाड़ा

- **बच्चों के मस्तिष्क विकास पर रहेगा विशेष फोकस**

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक 8वां पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस वर्ष पोषण पखवाड़े का मुख्य थीम जीवन के पहले छह वर्षों में मस्तिष्क का अधिकतम विकास निर्धारित किया गया है। पखवाड़े का औपचारिक शुभारंभ 9 अप्रैल को आंगनवाड़ी केन्द्रों और समुदाय स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाएगा। इस दौरान पोषण पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा।

पोषण पखवाड़े में मुख्य रूप से मातृ एवं शिशु पोषण, जन्म से 3 वर्ष तक मस्तिष्क विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन, 3 से 6 वर्ष तक खेल आधारित शिक्षा, बच्चों में स्क्रीन टाइम कम करने में परिवार और समुदाय की भूमिका तथा सशक्त आंगनवाड़ी निर्माण में सामुदायिक सहयोग जैसे विषयों पर गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।

वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार मानव मस्तिष्क का लगभग 85 प्रतिशत विकास जन्म से 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पोषण पखवाड़े में परिवारों और समुदायों में ऐसे व्यवहारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को मजबूत बनाते हैं।

संपादकीय

युद्ध विराम से तात्कालिक राहत

करीब सवा महीने से जारी ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में दो हफ्ते की युद्ध विराम की पहल सभी प्रभावित देशों के लिए तात्कालिक और बड़ी राहत है। हालांकि इस से यह मान लेना की समस्या का कोई स्थायी समाधान हो गया है, गलती होगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बन गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया। उल्लेखनीय है कि सीजफायर से पहले ट्रम्प ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वह उसकी पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे। उन्होंने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की भी धमकी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन के दखल के बाद संभव हो पाई। पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के सीजफायर का प्रस्ताव रखा था, जिसे ईरान ने स्वीकार कर लिया। समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे। ईरान भी हमले बंद करेगा। इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी। यह सीजफायर लेबनान समेत अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होगा। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच 10 अप्रैल को औपचारिक बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू होगी। गौर से देखें तो यह युद्ध विराम असल में ईरान की जीत और अमेरिका की हार ज्यादा लगती है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आगे कर अपने दांव चले हैं। सीजफायर के ऐलान के बाद ईरान की राजधानी में जश्न मनाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ईरान ने अमेरिका को 10 पाइंट का प्लान भेजा है। इस पर आगे बातचीत की जा सकती है। उधर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया है कि अमेरिका ने उसका 10 पॉइंट प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। काउंसिल के मुताबिक यह समझौता ईरान की शर्तों पर हुआ है और इसे देश की जीत बताया है। इस युद्ध के हाल के घटनाक्रमों से लगता है कि इस युद्ध विराम के लिए ईरान से ज्यादा अमेरिका ही बेताब था। क्योंकि उसे काफी आर्थिक नुकसान हो रहा था और घर में ट्रंप की भारी आलोचना हो रही थी। लिहाजा ट्रंप ने युद्ध से हाथ खींचने के लिए ही यह सीजफायर किया है। हालांकि इस मामले में आगे की बातचीत पाकिस्तान में होगी, लेकिन उसकी भूमिका इस मामले में मध्यस्थ से ज्यादा अमेरिकी एजेंट की ज्यादा लगती है। अगर समझौता हुआ तो पाकिस्तान को और पैसा कहीं न कहीं से मिल सकता है। इस बीच इजराइल की प्रतिक्रिया इस बातचीत को लेकर बहुत उत्सहवर्द्धक नहीं दिख रही है। आगे बातचीत किन मुद्दों पर होगी, कितनी सफल होगी, यह अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ईरान, रूस और चीन मिलकर अमेरिका को झुकाने में कामयाब हो गए हैं, यह मानना गलत नहीं होगा। अभी कई सवालों के जवाब मिलने हैं, जैसे कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का अधिकार मानेगा या नहीं, ईरान को युद्ध के कारण हुए नुकसान की भरपाई होगी या नहीं, खाड़ी देशों का अमेरिका पर कितना भरोसा कायम रहेगा, ये गुत्थियां अभी सुलझनी हैं। इतना तय है कि इस युद्ध के बाद नई वैश्विक व्यवस्था उभरेगी, जिसमें भारत को अपनी सार्थक भूमिका तलाशनी होगी। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में भारत का किरदार केवल एक दर्शक का है। हम मात्र अपने जहाज निकलवाने और सभी से बात करने के दावे तक सीमित हैं, जबकि पाकिस्तान ज्यादा सक्रिय भूमिका में दिख रहा है।

सियासी रण में पांच राज्य: सत्ता की कुर्सी किसके नाम?

नजरिया

योगेश कुमार गोयल
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों ने देश की राजनीति को उबाल पर ला दिया है। केरल से लेकर असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी तक सियासी हलचल अपने चरम पर है। रैलियों की गूंज, वादोंकी बरसात और आरोप-प्रत्यारोप के तीखे तीरों के बीच लोकतंत्र का यह उत्सव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। हर राजनीतिक दल अपने-अपने एजेंडे, घोषणापत्र और रणनीति के साथ मैदान में है और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। इस बार का चुनाव केवल सरकार बनाने का साधन नहीं बल्कि बीते पांच वर्षों के कामकाज का जनमत संग्रह और आनेवाले राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाला निर्णायक क्षण है। इन पांच राज्यों की कुल 824 विधानसभा सीटों पर लगभग 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि 116 लोकसभा सीटों के प्रभाव क्षेत्र से जुड़ा हुआ वह राजनीतिक रणक्षेत्र है,जो राष्ट्रीय राजनीति की धुरी को प्रभावित कर सकता है। चुनाव कार्यक्रम भी बेहद दिलचस्प है, असम, केरल और पुदुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में दो चरणों (23 और 29 अप्रैल) में वोट डाले जाएंगे। नतीजे 4 मई को घोषित होंगे और उसी दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने किसके पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया। इस बार का चुनावी परिदृश्य कई स्तरों पर जटिल और बहुआयामी है। सत्ताधारी दल जहां अपने विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और 'डबल इंजन' जैसे नारोंके सहारे जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं विपक्ष बेरोजगारी,महंगाई, सामाजिक असमानता और प्रशासनिक खामियों को मुद्दा बनाकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। यह संघर्ष अब केवल सत्ता का नहीं रहा बल्कि विचारधारा, नीतियों और विकास के मॉडलों की प्रतिस्पर्धा में बदल चुका है।

सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है पश्चिम बंगाल, जहां राजनीतिक तापमान सबसे ज्यादा है। 294 सीटों वाली विधानसभा में 6.44 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस नेप्रचंड बहुमत हासिल कर सत्ता पर कब्जा बनाए रखा था जबकि भाजपा ने मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस बार मुकाबला और अधिक तीखा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस अपने 'बंगाल मॉडल', महिला सशक्तिकरण योजनाओं और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों के साथ मैदान में है,वहीं भाजपा 'डबल

इंजन' सरकार के वादे और घुसपैठ जैसे मुद्दों को प्रमुखतादे रही है। रोजगार, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दे भी चुनावी विमर्श के केंद्र में हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यहांमुकाबला बेहद कांटे का होगा, एक तरफ ममता बनर्जी की राजनीतिक विरासत दांवपर है तो दूसरी ओर भाजपा के लिए यह पूर्वी भारत में विस्तार का सुनहरा अवसर है।

असम का चुनाव भी कम दिलचस्प नहीं है। 126 सीटों वाली विधानसभा में 2.25 करोड़ मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यहां मुख्य सवाल यही है कि क्याभाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर पाएगी या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वापसी का रास्ता तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमाके नेतृत्व में भाजपा विकास, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के मुद्दों कोलेकर जनता के बीच है। वहीं विपक्ष सीएए-एनआरसी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की सक्रियता ने इस चुनाव को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। असम में परिणाम न केवल राज्य की राजनीति बल्कि पूर्वोत्तर भारत में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करेंगे। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल की राजनीति अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का प्रभाव इतना गहरा है कि राष्ट्रीय दलों की भूमिका सीमित हो जाती है। 234 सीटों वाली विधानसभा में 5.67 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। पिछले चुनाव में डीएमके गठबंधन ने सत्ता हासिल कीथी और इस बार भी वह अपने 'द्रविड़ मॉडल', सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर मैदान में है। वहीं एआईए/डीएमके गठबंधन महंगाई, बिजलीसंकट और स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। इसके अलावा अभिनेता विजय की पार्टी का चुनावी मैदान में उतरना एक नया समीकरण बनासकता है, खासकर युवा मतदाताओं के बीच। केरल में 140 सीटों के लिए 2.7 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। यहां का चुना पारंपरिक रूप से सत्ता परिवर्तन के लिए जाना जाता रहा है लेकिन पिछले चुनाव में वाम मोर्चे ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया था। इस बार यदि वह तीसरी बार सत्ता में आता है तो यह एक नया राजनीतिक अध्याय होगा। वाम मोर्चा अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के मॉडल को प्रमुखता दे रहा है जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर हमलावर है। भाजपा भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होता जारहा है।

पुदुचेरी भले ही छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन यहां की राजनीति बेहद संवेदनशील और निर्णायक है। 30 सीटों वाली विधानसभा में 9.44 लाख मतदाता मतदान करेंगे। यहां गठबंधन राजनीति का महत्व सबसे अधिक है, जहां छोटे-छोटे वोट अंतर भी सत्ता की दिशा तय कर सकते हैं। पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन ने सत्ता हासिल की थी और इस बार भी वह अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस और क्षेत्रीय दल सत्ता वापसी के लिए संघर्षरत हैं। इन सभी राज्यों में एक समान बात यह है कि वोट प्रतिशत और सीटों का समीकरण हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार मामूली वोट अंतर भी भारी सीट अंतर में बदल जाता है। यही कारण है कि राजनीतिक दल बूथ स्तर तक अपनी रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार ने चुनावी अभियान को एक नई दिशा दी है, जहां नैरेटिव की लड़ाई केवल मैदान में नहीं बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लड़ी जा रही है।

चुनावी मुद्दों की बात करें तो इस बार कोई एक मुद्दा हावी नहीं है। रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि संकट और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रूप में सामने आ रहे हैं। यही विविधता इन चुनावों को और अधिक जटिल और रोचक बनाती है। राजनीतिक दृष्टि से इन चुनावों को 2029 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इन राज्यों से आने वाली 116 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यदि भाजपा असम में अपनी पकड़ बनाए रखती है, पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करती है और दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करती है, तो उसकी राष्ट्रीय स्थिति और सुदृढ़ हो सकती है। वहीं, यदि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अपनी सत्ता बरकरार रखती है तो ममता बनर्जी विपक्षी राजनीति की प्रमुख धुरी बनी रह सकती हैं। केरल में वाम मोर्चे की जीत वामपंथी राजनीति के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगी जबकि तमिलनाडु में डीएमके की निरंतरता द्रविड़ राजनीति की दिशा तय करेगी। कुल मिलाकर, यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला नहीं बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। मतदाता इस बार खामोश जरूर हैं लेकिन उनकी चुप्पी के भीतर गहराई से सोच-विचार और निर्णय की प्रक्रिया चल रही है। 4 मई को जब परिणाम सामने आएंगे, तभी यह स्पष्ट होगा कि किसने जनता की अपेक्षाओं को समझा और किसे आत्ममंथन की आवश्यकता है। लोकतंत्र का यह महापर्व एक बार फिर यह सिद्ध करने जा रहा है कि अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है और वही निर्णय देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है।

ईरान के प्रस्ताव से थमा युद्ध, संकट नहीं

सीजफायर

राजकुमार सिन्हा
लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

विगत 28 फरवरी से अमेरिका,इजरायल और ईरान के बीच चले युद्ध में डेडलाइन से डेढ़ घंटा पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर (संघर्ष विराम) का ऐलान कर दिया है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम स्वीकार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पोस्ट पर सीजफायर का ऐलान करते हुए कहा है कि ईरान के साथ सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन गई है और दो हफ्ते के अंदर समझौते के प्रस्ताव को आखिरी रूप दिया जाएगा। ट्रम्प ने कहा है कि उन्हें ईरान की तरफ से 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिला है जो बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोल देगा। ये भरोसा उन्हें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिया है।पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच 10 अप्रैल को बातचीत होगी। इसका ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया है। दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक समाधान तक पहुंचाने की कोशिश में पाकिस्तान की भूमिका एक मध्यस्थ के तौर पर अहम रही है।यह भी सच है कि पिछले एक साल में ईरान और अमेरिका के बीच दो बार बातचीत हुई है। दोनों ही बार बातचीत के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के पुलों, पावर प्लांट और अन्य प्रमुख ठिकानों को तबाह करने की जो चेतावनी और ईरान की 'सभ्यता समाप्त' करने की धमकी दी थी। इस चेतावनी और धमकी के बाद ईरान ने कहा है कि एक सभ्य राष्ट्र की संस्कृति, तर्क और अपने सही उद्देश्य पर विश्वास, बलपूर्वक दबाव की नीति पर भारी पड़ेगा।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ईरान अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। ईरान ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वह जवाबी कदम उठाएगा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस टकराव को लेकर चिंता बढ़ गई, क्योंकि इसका असर वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता था। ईरानी सरकार और सरकारी मीडिया अमेरिका के साथ हुए समझौते को वहां के शासन की एक बड़ी जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। क्योंकि वे अमेरिका और इजरायल के साथ 30 से अधिक दिनों तक चले इस युद्ध में टिके रहे और बच गए। इसलिए ईरान के इस बयान और ईरान के खुद को विजेता के रूप में पेश करने को अहम माना जा रहा है। युद्ध की शुरुआत में ही इस्लामिक रिपब्लिक के नेता अली खामेनेई और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ जनरलों की अमेरिकी-

इसराइली हमलों में मौत हो गई थी। यह लड़ाई वहां के शासन के लिए अस्तित्व के लिए खतरा था और एक अस्तित्व की लड़ाई थी। ईरानी मीडिया के अनुसार, इस प्रस्ताव में 10 बिंदु शामिल हैं, जिसमें अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता और भविष्य में ईरान पर आक्रमण नहीं करने की मजबूत अंतरराष्ट्रीय गारंटी मिले। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण जारी रहेगा और होर्मुज को खुला रखने पर ईरान अपनी शर्तें तय करेगा। कोई भी विदेशी ताकत (खासकर अमेरिका) इसके इस्तेमाल पर दबाव नहीं डाल सकेगी। यूरेनियम संवर्धन की स्वीकृति। ईरान पर अमेरिका सभी प्राथमिक प्रतिबंधों को हटाएगा। इजरायली अटैक रोकने की मांग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्तावों को समाप्त करना।ईरान को युद्ध में ईरान हुए सभी तरह के बुनियादी नुकसान का मुआवजा (क्षतिपूर्ति) दी जाए। क्षेत्र से अमेरिकी लड़ाकू बलों की वापसी और खाड़ी क्षेत्र में सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करना। लेबनान और गाजा में भी युद्ध की समाप्ति और लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ लड़ाई समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम की शर्तें शामिल हैं।

ईरान युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे 'वैश्विक तेल बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा आपूर्ति व्यवधान' बताया है। इस संघर्ष ने 1970 के दशक के ऊर्जा संकट की याद दिला दी है, जिसमें आपूर्ति की गंभीर कमी, मुद्रा अस्थिरता, मुद्रास्फीति और मंदी तथा आर्थिक संकट का खतरा बढ़ गया है। युद्ध ने खाडी सहयोग परिषद के आर्थिक मॉडल को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इस युद्ध ने यूरोप के लिए दूसरा बडा ऊर्जा संकट और उसके बाद आर्थिक संकट पैदा कर दिया है, मुख्य रूप से कतर देश के द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के निलंबन और होमुर्ज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण उत्पन्न हुआ है। इस संकट ने यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ में औद्योगिक उत्पादन को और भी प्रभावित किया है, जहां रसायन और इस्पात निर्माताओं ने बिजली और कच्चे माल की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए 30 प्रतिशत तक अधिभार लगाया है।दुनिया के बाकी हिस्सों में अफरा-तफरी मची हुई है और पेट्रोलियम के वितरण में भारी व्यवधान उत्पन्न हो गया है। दुनिया की जीडीपी को अब तक करीब 54.88 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। इस तबाही से वॉल स्ट्रीट से लेकर दलाल स्ट्रीट तक हर तरफ हाहाकार मचा है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (सीएसआईएस) वाशिंगटन के मुताबिक, इस युद्ध में अब तक अमेरिका को 7.49 लाख करोड़ रुपये (80.4 बिलियन डॉलर) स्वाहा हो चुका है। युद्ध शुरू होने के बाद से भारतीय निवेशकों के करीब 37 लाख करोड़ रुपये डूब चुके हैं।कच्चे माल और ऊर्जा की लागत बढ़ने से दुनिया भर में वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे मंदी का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच यह संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं था, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की जड़ों को हिला देने वाला घटनाक्रम साबित हुआ है।ईरान द्वारा इस समझौते को अपनी 'कूटनीतिक जीत' के रूप में प्रस्तुत करना और अमेरिका द्वारा इसे एक व्यवहारिक समाधान के रूप में स्वीकार करना यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष लंबे संघर्ष के बाद किसी मध्य मार्ग की ओर बढ़ने को मजबूर हुए हैं। हालांकि, प्रस्ताव में शामिल शर्तें जैसे प्रतिबंधों का हटना, परमाणु कार्यक्रम की स्वीकृति, होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण और क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य वापसी इतनी जटिल और विवादास्पद है कि उनका पूर्ण क्रियान्वयन आसान नहीं होगा।अंततः, यह संघर्ष एक महत्वपूर्ण सबक देता है कि युद्ध भले ही शक्ति का प्रदर्शन करता हो, लेकिन स्थायी समाधान केवल संवाद, आपसी विश्वास और संतुलित कूटनीति से ही संभव है।

डिग्री नहीं, स्किल ही फ्यूचर

शिक्षा

समराज चौहान
शोधार्थी, असम यूनिवर्सिटी

आज का समय तेजी से बदल रहा है। जिस दुनिया में कभी डिग्री को सफलता की कुंजी माना जाता था, आज उसी दुनिया में कौशल, सोच और अनुकूलन क्षमता अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। यह परिवर्तन केवल शिक्षा प्रणाली में ही नहीं, बल्कि समाज, रोजगार और जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब यह सवाल कम महत्वपूर्ण हो गया है कि आपके पास कौन-सी डिग्री है, और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि आप क्या कर सकते हैं।पहले के समय में उच्च शिक्षा प्राप्त करना ही एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। एक अच्छी डिग्री मिलने का मतलब था एक स्थिर नौकरी और सुरक्षित भविष्य। माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। उस समय यह सोच काफी हद तक सही भी थी, क्योंकि अवसर सीमित थे और प्रतिस्पर्धा कम थी। लेकिन आज की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है।

अब लाखों छात्र हर साल डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से अपने करियर में संघर्ष करते दिखाई देते हैं।इसका मुख्य कारण यह है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली आज भी काफी हद तक सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित है। छात्र किताबों से जानकारी तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उन्हें उस ज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। वे परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी समस्या का व्यावहारिक समाधान निकालना होता है, तो वे अक्सर असमंजस में पड़ जाते हैं।यही वह बिंदु है जहां 'कौशल' की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कौशल वह क्षमता है जो व्यक्ति को किसी कार्य को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाती है। यह केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, समस्या-समाधान, रचनात्मक सोच और टीमवर्क जैसी क्षमताएं भी शामिल हैं। आज की कंपनियां ऐसे कर्मचारियों की तलाश में हैं जो केवल पढ़े-लिखे न हों, बल्कि काम करने में सक्षम भी हों।

इसके साथ ही, आज के युग में बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता भी अत्यंत आवश्यक हो गई है। तकनीक के क्षेत्र में हो रहे तेजी से बदलाव ने कई पारंपरिक नौकरियों को समाप्त कर दिया है और नई-नई नौकरियों का निर्माण किया है। ऐसे में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो इन परिवर्तनों को स्वीकार करे और खुद को समय के साथ अपडेट करता रहे।

एक और महत्वपूर्ण पहलू है 'अनुभव' यानी अनुभव। अनुभव वह शिक्षक है जो हमें वास्तविक दुनिया की सच्चाइयों से परिचित कराता है। यह हमें सिखाता है कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर और सही तरीके से उपयोग करना भी जरूरी है। इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क, पार्ट-टाइम जॉब्स और फील्ड एक्सपीरियंस जैसे माध्यम छात्रों को वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि समस्या डिग्री में नहीं है, बल्कि उस मानसिकता में है जो यह मानती है कि केवल एक डिग्री ही जीवन बदल सकती है। यह सोच व्यक्ति को सीमित कर देती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है। इसके विपरीत, यदि व्यक्ति यह समझ ले कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, तो वह अपने जीवन में अधिक सफल हो सकता है।

आज के समय में 'विकासशील मानसिकता' अपनाना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे, अपनी गलतियों से सीखे और खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करे। जो लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है, वे धीरे-धीरे पीछे छूट जाते हैं। वहीं, जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, वे आगे बढ़ते रहते हैं।इसके अलावा, 'सुविधा क्षेत्र' से बाहर निकलना भी सफलता के लिए आवश्यक है। जब तक हम अपनी सीमाओं को चुनौती नहीं देंगे, तब तक हम अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। जोखिम लेना, असफलताओं का सामना करना और उनसे सीखना ही हमें मजबूत बनाता है।

आज की दुनिया में सफलता का नया मापदंड बदल चुका है। अब यह जरूरी नहीं है कि आपके पास सबसे बड़ी डिग्री हो, बल्कि यह जरूरी है कि आपके पास सही कौशल और सही दृष्टिकोण हो। डिजिटल युग में इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने सीखने के अनगिनत अवसर प्रदान किए हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार नए कौशल सीख सकता है और अपने करियर को नई दिशा दे सकता है।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि डिग्री का महत्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन यह अब सफलता की गारंटी नहीं रही। यह केवल एक प्रारंभिक कदम है, जो आपको अवसरों तक पहुंचाता है। उन अवसरों का लाभ उठाना और उन्हें सफलता में बदलना पूरी तरह आपकी मेहनत, कौशल और सोच पर निर्भर करता है। इसलिए, आज के युवाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे केवल डिग्री प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि अपने कौशल को विकसित करने, अनुभव प्राप्त करने और खुद को लगातार अपडेट करने पर भी ध्यान दें। क्योंकि अंत में, दुनिया आपको आपकी डिग्री से नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत से पहचानेगी।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

समझौता करवा लो...

डॉ. प्रदीप मिश्र
लेखक व्यंग्यकार हैं।

आपको जानकर खुशी होगी कि आपके सेवार्थ हमने बहुमंजिला 'समझौता मॉल' खोल रखा है। कैसा भी विवाद हो, हम बातचीत, कहानियों और अभिनय से समाधानकारी समझौता करवा देते हैं।

हमारे वातानुकूलित मॉल में 'मैरिज डिस्प्यूट सॉल्यूशन' के डिपार्टमेंट सबसे अधिक भीड़ होती है। पति-पत्नी, लीव-इन रिलेशनशिप युगल, प्रेमी-प्रेमिकाज्अन्य, सभी के मध्य उत्पन्न विवाद को समझा-बुझाकर समझौते की देहलीज पर लाने में हमने विशेषज्ञता हासिल कर रखी है। हम कहते हैं, 'पॉल्टिक्स की तरह पति-पत्नी के संबंधों में न स्थाई दुश्मनी होती है, न स्थाई दोस्ती। रिश्तों को निर्बाध चलाने के लिए यू-टर्न मारने की कावायत आना जरूरी है।' विवादग्रस्त-युगल को हम यू-टर्न मारने में विख्यात जननायकों की यू-टरनक कथाएं सुनाते हैं। युगल प्रभावित होते हुए कहते हैं, 'जब नेताजी इतने विवाद के बाद यू-टर्न ले सकते हैं, तो हम लोग किस यू-मोड़ के टर्न हैं?' इस तरह हम युगल के बीच समझौता फाइनल करते हैं।

सास-बहू के सनातन विवाद के निराकरण में हम उन्हें दो कट्टर दुश्मन नेताओं के प्रेमात्मक गठबंधन की कथा सुनाते हैं। दोनों एक-दूसरे को फूटी आंख से नहीं देखना चाहते थे, लेकिन मंच पर हाथ उठाकर एकता दिखाते है और सफलतापूर्वक सरकार चलाते हैं। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सास और बहू को भी विरोध के बावजूद हित साधने के लिए विवादों को कूड़े में डालना चाहिए।

हम देशों में भी समझौता कराते हैं। हम लड़ने वाले मुल्कों से बात नहीं करते। जिनका युद्ध से सीधा संबंध नहीं है, समझौते के लिए उनको बुलाते हैं। अमेरिका-इजरायल और ईरान में लड़ाई हो रही है तो हम लल्लूजी, पंजूजी और लफंगू साहब को बुलाते हैं। हम उन्हें समझाते हैं, 'लड़ाई रुकनी चाहिए। यह मानवता के विरूद्ध है। सारे विश्व को परेशानी हो रही है। बातचीत से मसले हल होने चाहिए...।' फिर हम ऐलान करते हैं, हमने समझौता कराया। विशाल समझौता। समझौता करने आए तीनों लड़ाकों ने हमारी बात मानी। आने वाले समय में लड़ाई रुकेगी। हम कामयाब हुए। अब आप हमारे मॉल की फीस चुकाइए और समझौता उठा ले जाइए।' पत्रकार पूछते हैं, ' इन फंटूशों से समझौता करके क्या मिलेगा? ये न तो तीन अरब में हैं न तेरह अरब में?' हमने कहा , ' यह तो अभी समझौते का 'स' था। फिर 'म' आएगा । इसमें नमूनाजी, नगीना साहब और निठल्लाजी पधारेंगे। इसके बाद 'झ' आएगा। इसमें हमने ऐसाजी, वैसा साहब और कैसा कुमार को न्यौता भेजा है। अंत में जब कभी 'त' आएगा तब देखना ट्रंपजी, याहू भाई और ईरान में तब कार्य करने वाले शासक आएंगे।' कहकर हमने मॉल के सामने साइन बोर्ड पर 'समझौता' और बड़े से लिखवा दिया।

भारत में कामकाज की स्थिति-2026

कुमार सिद्धार्थ

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

देश का युवा भविष्य : शिक्षा, रोजगार और अधूरा वादा

28 फीसदी तक पहुंच चुकी है और इसमें लड़कियों की भागीदारी खासतौर पर बढ़ी है। हालांकि, पुरुषों के नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 2017 के 38 फीसदी से घटकर वर्ष 2024 के अंत तक 34 फीसदी रह गई है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि युवा वयस्क अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए कमाने के अवसर तलाशने लगते हैं। यह बदलाव सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह संकेत देता है कि शिक्षा अब समाज के व्यापक वर्गों तक पहुंच रही है। लेकिन इस प्रगति के साथ एक गहरी विडंबना भी जुड़ी है- शिक्षा बढ़ तो रही है, लेकिन रोजगार के अवसर उसी अनुपात में नहीं बढ़ पा रहे हैं।

भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। यह तथ्य अक्सर गर्व के साथ दोहराया जाता है कि देश की बड़ी आबादी कार्यशील आयु वर्ग में है और यही भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब यही युवा, खासकर शिक्षित युवा, रोजगार के लिए भटकते नजर आते हैं, तब यह 'जनसांख्यिकीय लाभ' एक कठिन प्रश्न बनकर सामने खड़ा हो जाता है।

हाल ही में जारी 'भारत में कामकाज की स्थिति-2026' रिपोर्ट ने इस जटिल वास्तविकता को ठोस तथ्यों के साथ सामने रखा है और देश के युवाओं की शिक्षा, रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े कई अहम रुझानों को रेखांकित किया है।

अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी रिपोर्ट केवल तथ्यों का संकलन नहीं, बल्कि उस संकट का दस्तावेजीकरण है, जिसमें आज का शिक्षित युवा जूझ रहा है। उसके पास उपाधियाँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, सपने हैं, लेकिन अवसर सीमित हैं।

पिछले चार दशकों में भारत में उच्च शिक्षा का दायरा तेजी से बढ़ा है। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, उच्च शिक्षा में नामांकन दर अब 28 फीसदी तक पहुंच चुकी है और इसमें लड़कियों की भागीदारी खासतौर पर बढ़ी है। हालांकि, पुरुषों के नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 2017 के 38 फीसदी से घटकर वर्ष 2024 के अंत तक 34 फीसदी रह गई है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि युवा वयस?क अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए कमाने के अवसर तलाशने लगते हैं।

यह बदलाव सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह संकेत देता है कि शिक्षा अब समाज के व्यापक वर्गों तक पहुंच रही है। लेकिन इस प्रगति के साथ एक गहरी विडंबना भी जुड़ी है- शिक्षा बढ़ तो रही है, लेकिन रोजगार के अवसर उसी अनुपात में नहीं बढ़ पा रहे हैं।

रिपोर्ट बताती है कि 20 से 29 वर्ष के 6.3 करोड़ स्नातकों में से लगभग 1.1 करोड़ बेरोजगार हैं। यह युवा रोजगार की वास्तविकता है, जो वर्षों की पढ़ाई के बाद भी रोजगार से वंचित हैं। रिपोर्ट बताती है कि युवाओं को जो नौकरियां मिलती भी है, वह अक्सर अस्थायी, कम वेतन वाली या कौशल के अनुरूप नहीं होती। स्नातक होने के एक वर्ष के भीतर केवल सात फीसदी युवाओं को ही स्थायी वेतन वाली नौकरी मिल पाती है।

यह धारणा लंबे समय तक बनी रही कि शिक्षा ही बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता है। लेकिन आज स्थिति उलट दिखती है। रिपोर्ट के अनुसार, 15 से 25 वर्ष के स्नातकों में बेरोजगारी दर लगभग 40 फीसदी है, जबकि 25 से 29 वर्ष के युवाओं में यह करीब 20 फीसदी है।

यह स्थिति एक संकेत है कि शिक्षा और रोजगार के बीच का संबंध कमजोर हो गया है। डिग्री/उपाधि होने के बावजूद नौकरी नहीं मिलना युवाओं में निराशा और असंतोष को जन्म देता है। आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल बेरोजगारी नहीं, बल्कि 'अधूरा रोजगार' भी है। बड़ी संख्या में युवा ऐसे काम कर रहे हैं, जो उनकी शिक्षा और कौशल के अनुरूप नहीं हैं। कई इंजीनियर डिलीवरी का काम कर रहे हैं, स्नातक डाटा एंट्री या अस्थायी अनुबंधों पर निर्भर हैं। यह केवल व्यक्तिगत हानि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संसाधनों की भी बर्बादी है। जिस शिक्षा पर इतना निवेश किया गया, वह अपेक्षित उत्पादकता में परिवर्तित नहीं हो पा रही है।

रिपोर्ट इस ओर भी इंगित करती है कि केवल शिक्षा का विस्तार पर्याप्त नहीं है, उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सन् 2010 से 2021 के बीच प्रति लाख युवाओं पर कॉलेजों की संख्या 29 से बढ़कर 45 हो गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की संख्या में भी लगभग 300 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद क्षेत्रीय असमानताएं बनी हुई हैं और शिक्षकों की कमी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। निर्धारित मानकों के मुकाबले निजी और सरकारी कॉलेजों में शिक्षक-छात्र अनुपात काफी अधिक है।

लेकिन इन संस्थानों से निकलने वाले युवाओं के पास वह कौशल नहीं है जिसकी मांग उद्योगों में है। यह स्थिति बताती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी भी 'डिग्री केंद्रित' है, न कि 'कौशल केंद्रित'। रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि उच्च शिक्षा में गरीब परिवारों की भागीदारी बढ़ी है जो वर्ष 2007 के 8 फीसदी से बढ़कर 2017 में 15 फीसदी हो गई है। हालांकि यह एक सकारात्मक परिवर्तन दिखता है, लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या इन युवाओं को शिक्षा के बाद समान अवसर मिल रहे हैं?

महंगे पेशेवर पाठ्यक्रम अब भी संपन्न वर्ग के लिए अधिक सुलभ हैं। परिणामस्वरूप, बेहतर वेतन और स्थायी रोजगार के अवसर भी उसी वर्ग तक सीमित रह जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा में समानता बढ़ने के बावजूद रोजगार में असमानता बनी रहती है।

भारत की अर्थव्यवस्था में भी बदलाव हो रहा है। युवा कृषि से हटकर सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), मोटर वाहन और व्यावसायिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जबकि पेशेवर क्षेत्र में जाति एवं स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव कम हुआ है। लेकिन इन क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन की गति अपेक्षित नहीं है। एक ओर उच्च कौशल वाली नौकरियां सीमित हैं, दूसरी ओर कम कौशल वाले कार्यों में अस्थिरता और कम वेतन की समस्या है। यह असंतुलन युवाओं के सामने एक कठिन स्थिति पैदा करता है वे न तो पूरी तरह रोजगार पा रहे हैं, और न ही अपने कौशल का सही उपयोग कर पा रहे हैं।

देश के पास सीमित वक्त है, जिसमें वह अपने जनसांख्यिकीय लाभ को आर्थिक विकास में बदल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 के बाद कामकाजी आयु वर्ग की आबादी का अनुपात घटने लगेगा। इसका मायने है कि आने वाले कुछ वर्षों में रोजगार सृजन को गति देना आवश्यक है। यदि यह अवसर चूक गया, तो बड़ी संख्या में बेरोजगार और असंतुष्ट युवा सामाजिक और आर्थिक संकट का कारण बन सकते हैं।

इस गंभीर समस्या का समाधान केवल एक क्षेत्र में सुधार से संभव नहीं है। इसके लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। पहला, शिक्षा और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना होगा। पाठ्यक्रमों को वास्तविक जरूरतों के अनुरूप बनाना जरूरी है। दूसरा, कौशल विकास को प्राथमिकता देनी होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारनी होगी। तीसरा, रोजगार सृजन को नीति के केंद्र में रखना होगा। केवल विकास दर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि रोजगार आधारित विकास की दिशा में कदम उठाने होंगे। चौथा, उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना होगा। युवाओं को केवल नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार सृजक बनने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। पांचवां, क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए लक्षित नीतियां बनानी होंगी।

भारत के युवाओं के सामने आज जो स्थिति है, वह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संकट भी है। यह समझना जरूरी है कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन और रोजगार के लिए तैयारी का साधन है। यदि यह तैयारी अधूरी रह जाती है, तो उसका परिणाम बेरोजगारी, असंतोष और सामाजिक असंतुलन के रूप में सामने आता है। इसी कारण शिक्षा के माध्यम से जो उम्मीदें पैदा होती हैं, जब वे पूरी नहीं होतीं, तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। रिपोर्ट इस महत्वपूर्ण बात को रेखांकित करती है कि यदि शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को समय रहते नहीं भरा गया, तो देश का सबसे बड़ा संसाधन ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। अब आवश्यकता है कि इस मुद्दे को केवल तथ्यों के स्तर पर नहीं, बल्कि नीति और क्रियान्वयन के स्तर पर गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि यह केवल रोजगार का प्रश्न नहीं है यह देश के भविष्य का प्रश्न है।

डिजिटल जनगणना 2027

अरुण कुमार डनायक

लेखक समाजसेवी हैं।

भारत की प्रशासनिक क्षमता का नया अध्याय

इस चरण में भवन की पहचान, निर्माण सामग्री, स्वामित्व, निवासियों की संख्या, जल-स्वच्छता-विद्युत-ईंधन की उपलब्धता, घरेलू परिसंपत्तियों तथा परिवार प्रमुख, लिंग और दांपत् स्थिति जैसे जनसांख्यिकीय विवरणों सहित कुल 33 प्रश्न सम्मिलित होंगे, जिनमें सहजीवन को भी स्थिर संबंध मानकर विवाहित की श्रेणी में रखा जाएगा। फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से आयु, शिक्षा, व्यवसाय, प्रवासन, प्रजनन, धर्म, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, तथा सांस्कृतिक विशेषताओं जैसे व्यक्ति-स्तरीय विवरण संकलित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मकान सूचीकरण जनगणना 1 मई से 30 मई, 2026 तक आयोजित की जाएगी, जबकि स्व-गणना की अवधि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2026 तक रहेगी।

भारत में पाँच वर्षों के विलंब के बाद आरम्भ हुई जनगणना 2027 न केवल आकार में विश्व की सबसे बड़ी है, बल्कि तकनीकी ढाँचे और सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों के कारण भी अभूतपूर्व है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जाति आधारित गणना को सम्मिलित किया जाना, डिजिटल माध्यमों का व्यापक उपयोग, स्वयंगणना का विकल्प, परिसीमन व आरक्षण जैसी नीतिगत प्रक्रियाओं पर इसके दूरगामी प्रभाव–ये सभी तत्व इस जनगणना को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए रू. 11,718.24 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जिनमें गणनाकर्मियों के मानदेय, प्रशिक्षण, आईटी अवसंरचना और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ शामिल हैं। जनगणना 2027 का आयोजन 01.01.2026 की स्थिति के अनुसार देश के 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, 7,092 उप-जिलों, 5,128 सांविधिक नगरों (शहरी एवं प्रशासनिक ढाँचा युक्त), 4,580 जनगणना नगरों (स्थानीय प्रशासनिक इकाई विहीन) तथा लगभग 6,39,902 ग्रामों में किया जाएगा।

भारत में आधुनिक जनगणना 1881 में पहली बार पूरे देश में समन्वित रूप से संपन्न हुई। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली जनगणना आयोजित की गई। अब, 2027 की जनगणना स्वतंत्र भारत की आठवीं और कुल सोलहवीं जनगणना है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें लगभग 30 लाख गणनाकर्मी स्मार्टफ़ोन आधारित मोबाइल ऐप से सीधे डेटा अपलोड करेंगे। यह ऐप हिन्दी-अंग्रेज़ी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है और बिना इंटरनेट के भीदूरदराज़ क्षेत्रों में कार्य करता है। यद्यपि गणनाकर्मी पूर्ववत् घर-घर जाकर विवरण संकलित करेंगे, इस बार उत्तरदाताओं को स्व-गणना का विकल्प भी दिया गया है। नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर लॉगिन कर स्थान चिन्हित, गृह विवरण भरने और सूचना प्रेषित करने पर एक विशिष्ट स्व-गणना आईडी प्राप्त करेंगे, जिसे गणनाकार को देने पर अभिलेख में सम्मिलित कर लिया जाएगा। यह सुविधा समय बचाते हुए नागरिकों को अपनी सुविधा अनुसार जानकारी भरने का अवसर देती है।

डिजिटल जनगणना भारत की प्रशासनिक और तकनीकी क्षमता को नई दिशा देने वाला कदम है, जो पारदर्शी, त्वरित और नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था के भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। हालांकि डिजिटल जनगणना की सफलता डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने के साथ-साथ गणनाकर्मियों के प्रशिक्षण, डिजिटल दक्षता और जमीनी स्तर की व्यावहारिक चुनौतियों के प्रभावी समाधान पर भी निर्भर करेगी।

जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी– पहले चरण में गृहसूचीकरण एवं आवास जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच राज्यों की सुविधा के अनुसार 30 दिनों की अवधि में की जायेगी। इस चरण में भवन की पहचान, निर्माण सामग्री, स्वामित्व, निवासियों की संख्या, जल-स्वच्छता-विद्युत-ईंधन की उपलब्धता, घरेलू परिसंपत्तियों तथा परिवार प्रमुख, लिंग और दांपत् स्थिति जैसे जनसांख्यिकीय विवरणों सहित कुल 33 प्रश्न सम्मिलित होंगे, जिनमें सहजीवन को भी स्थिर संबंध मानकर विवाहित की श्रेणी में रखा जाएगा। फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से आयु, शिक्षा, व्यवसाय, प्रवासन, प्रजनन, धर्म, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, तथा सांस्कृतिक विशेषताओं जैसे व्यक्ति-स्तरीय विवरण संकलित किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मकान सूचीकरण जनगणना 1 मई से 30 मई, 2026 तक आयोजित की जाएगी, जबकि स्व-गणना की अवधि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2026 तक रहेगी। 1931 के बाद पहली बार द्वितीय चरण में जाति आधारित गणना की जाएगी, जो इस जनगणना का सबसे चर्चित और विवादास्पद पहलू है, विशेषकर क्योंकि भाजपा प्रारंभ में इसके विरोध में थी। 1951 में 'सामाजिक विभाजन' की आशंका के कारण इसे बंद कर दिया गया था और तब से केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित सीमित जानकारी ही एकत्र होती रही। किंतु वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने इस प्रश्न को पुनः केंद्र में ला दिया है; विस्तृत जाति आँकड़ों के अभाव में नीति निर्माण 'अंधेरे में तीर चलाने' जैसा हो गया है, जिससे न संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित हो पा रहा है और न ही वंचित समुदायों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो रही है।दूसरी ओर, विरोधियों का तर्क है कि जातिगणना से जातीय पहचानें कठोर होंगी, सामाजिक विभाजन गहरे होंगे और जाति को एक स्थायी सरकारी मान्यता मिल जाएगी। यह बहस केवल शैक्षणिक नहीं है; इसका सीधा प्रभाव आरक्षण नीति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अन्य पिछड़ा वर्ग उपवर्गीकरण जैसे मुद्दों पर पड़ेगा।

इस जनगणना के सामाजिक प्रभावों के साथ इसके राजनीतिक परिणाम भीमहत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसके बाद परिसीमन के तहत जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ पुनर्निर्धारित होंगी, और दक्षिण भारत के राज्यों को आशंका है कि इससे उत्तर भारत को अत्यधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान भी इसी प्रक्रिया के उपरांत लागू होगा। इसी संदर्भ में नागरिकता से जुड़े प्रश्न भी उभरते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के पूरे देश में लागू होने की घोषणा तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम के कारण यह आशंका है कि जनगणना के आंकड़ों का उपयोग नागरिकता निर्धारण में किया जासकता है। यह पहली बार होगा जब जनगणना का प्रत्यक्ष संबंध नागरिकता से स्थापित हो सकता है, जिससे कुछ समुदायों में गंभीर चिंता उत्पन्न हुई है। सत्तारूढ़ दक्षिणपंथी सरकार पर यह आरोप लगते रहें हैं कि वह मुस्लिम समुदाय के प्रति वैमनस्य को बढ़ावा दे रही है। पिछले वर्ष अनेक अवैध प्रवासियों को मनमाने ढंग से देश से बाहर भेजा गया। कुछ मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने आरोप लगाया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को अंडमान सागर के निकट छोड़ दिया गया, जिससे भारत की प्रवासन नीतियों और नागरिकता बहसों में चिंताएँ तीव्र हुईं। इसके अलावा, कई भाजपा नेता मात्र 14 प्रतिशत आबादी वाले मुसलमानों को देश के लिए खतरा बताकर यह मिथक फैलाते रहे हैं कि वे शीघ्र ही हिंदू जनसंख्या को पीछे छोड़ देंगे, जिससे भेदभाव और सामाजिक असुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। कोविड-19 के कारण 2021 की जनगणना स्थगित होने से डेटा तंत्र में गंभीर रिक्तताएँ उत्पन्न हुईं, क्योंकि अधिकांश सर्वेक्षण जनगणना को ही अपने सैम्पलिंग फ्रेम के रूप में उपयोग करते हैं; इसके पुराने होने से उनकी प्रतिनिधिकता प्रभावित होती है और नीति निर्माण में त्रुटियाँ बढ़ती हैं। पिछले दशक में डेटा पारदर्शिता पर उठे प्रश्नों–डेटा साझा न करने, गुणवत्ता के नाम पर त्याग और बार-बार पद्धति परिवर्तन–को देखते हुए जनगणना को जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी ढंग से संचालित किया जाना आवश्यक है।

जनगणना 2027 केवल एक सांख्यिकीय अभ्यास नहीं, बल्कि वह आधार है जिसके माध्यम से नीतियाँ निर्मित होंगी, संसाधनों का वितरण तय होगा और भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित होगी। भारत की यह ऐतिहासिक जनगणना–डिजिटल तकनीक, स्वयंगणना, जाति आधारित डेटा और राजनीतिक सामाजिक प्रभावों के साथ–निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में देश की संरचना और संवाद को गहराई से प्रभावित करेगी।

प्रकृति

संजीव शर्मा

बुरांश में आग भी है और यौवन का फाग भी..

मार्च और अप्रैल के महीनों में खिलने वाले बुरांश से पहाड़ मनमोहक हो जाते हैं। गर्मियों के दिनों में ऊंची पहाड़ियों पर बुरांश के सुर्ख फूलों के गुच्छों से यहां का परिदृश्य लाल हो जाता है। बताया जाता है कि बुरांश के फूल कई रंग के होते हैं लेकिन हमें तो केवल मासूमियत से भरा लाल बुरांश ही देखने को मिला। बुरांश केवल अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत से जुड़े फायदोंऔर सांस्कृतिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। देवभूमि हिमाचल में इसे प्रकृति का आशीर्वाद माना जाता है। स्थानीय लोग इसे बराह या ब्रांस जैसेनामों से भी पुकारते हैं। वसंत के मौसम में इसके फूलों का खिलना एक उत्सव की तरह होता है, जो पहाड़ी जीवन की जीवंतता को दर्शाता है।

देश के मैदानी इलाकों में इन दिनों जहां पलाश और गुलमोहर दहक रहे हैं, वहीं पहाड़ों पर बुरांश अपनी मुस्कराहट से लालिमा बिखेर रहा है। हिमाचल प्रदेश में पेड़ों पर झुंड के झुंड बुरांश पहाड़ों को खूबसूरत बना रहे हैं। देश के अन्य पर्वतीय राज्यों का हाल भी शायद ऐसा ही होगा। पहाड़ों पर वैसे तो देवदार का कब्जा है और वे अपनी ऊंचाई से कई बार पहाड़ों के शिखर को भी बोना साबित करते नजर आते हैं लेकिन देवदार के बीच से झांकता लाल रंग का बुरांश खूबसूरती से हमारे दिल में उतर जाता है। बुरांश पर कवियों ने खूब कलम चलाई है। सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने तो कुमाऊंनी में लिखा है-

'सार जंगल में त्वे जस
क्वे न्हां रे बुरांश,
खिलन क्ये छै जंगल
जस जलि जा, सल्ल छ, दयार छ,
पई छ, अयार छ,
सबन में पुंगनक भार छ,
पर त्वी में दिलै की आग छ,
त्वी में जवानिक फाग छ।'

इसका तात्पर्य है कि बुरांश तुझ सा सारे जंगल में कोई नहीं है। जब तू फूलता है, सारा जंगल मानो जल उठता है। जंगल में और भी कई तरह के वृक्षहैं पर एकमात्र तुझमें ही दिल की आग और यौवन का फाग दोनों मौजूद हैं।

पहाड़ी इलाकों की प्रकृति और प्रवृत्ति से अनजान लोगों की सुविधा के लिए बताते चले कि बुरांश एक खूबसूरत और औषधीय गुणों से भरपूर फूलों वाला पेड़ है जो मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पूरीतरह से भारतीय है और पूरे हिमालयी इलाकों के साथ साथ कई अन्य देशों में भी पाया जाता है। यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल है। जबकि उत्तराखंड में इसेराजकीय वृक्ष तो नेपाल में राष्ट्रीय पुष्प का रुतबा हासिल है।

बुरांश को वैज्ञानिक रूप से रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम के नाम से जाना जाता है। रोडोडेंड्रोन दो ग्रीक शब्दों रोडन यानि गुलाब और डेंड्रोन अर्थात् पेड़ से बना है। जिसका अर्थ है गुलाब का पेड़। दरअसल बुरांश दूर से लाल गुलाबकी तरह ही खूबसूरत नज़र आता है। सामान्य तौर पर मार्च और अप्रैल के महीनों में खिलने वाले बुरांश से पहाड़ मनमोहक हो जाते हैं। गर्मियों के दिनों में ऊंची पहाड़ियों पर बुरांश के सूर्ख फूलों के गुच्छों से यहां का परिदृश्य लाल हो जाता है। बताया जाता है कि बुरांश के फूल कई रंग के होते हैं लेकिन हमें तो केवल मासूमियत से भरा लाल बुरांश ही देखने को मिला।

बुरांश केवल अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत से जुड़े फायदोंऔर सांस्कृतिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। देवभूमि हिमाचल में इसे प्रकृति का आशीर्वाद माना जाता है। स्थानीय लोग इसे बराह या ब्रांस जैसेनामों से भी पुकारते हैं। वसंत के मौसम में इसके फूलों का खिलना एक उत्सव की तरह होता है, जो पहाड़ी जीवन की जीवंतता को दर्शाता है।

बुरांश के फूलों और पत्तियों में कई औषधीय गुण होते हैं, जिनका उपयोगआयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में सदियों से किया जाता रहा है। इसमेंएंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-वायरल गुण पाए जाते हैं। बुरांश के फूलों से बना शरबत हृदय रोगियों के लिए लाभकारीमाना जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने और रक्त संचार को बेहतर करनेमें मदद करता है। इसमें आयरन की अच्छी मात्रा होती है, जो खून की कमी को दूर करने और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक है। फूलों में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है और जोड़ों के दर्द में राहत देता है।

बुरांश के फूलों का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। इसके फूलों सेजूस, शरबत, जैम और चटनी बनाते हैं। बुरांश का महत्व केवल औषधीय ही नहीं,बल्कि सांस्कृतिक भी है। बुरांश के पेड़ नमी को संरक्षित करने और पेयजल स्रोतों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, जलवायु परिवर्तन के कारण इसके खिलने का समय प्रभावित हो रहा है। कई बार यहसामान्य से पहले खिल जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का संकेत माना जा रहा है।

कुल मिलाकर बुरांश का फूल न केवल प्रकृति की खूबसूरती का प्रतीक है,बल्कि एक औषधीय खजाना भी है। यह पहाड़ी इलाकों में लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। तभी तो कवियत्री हनी हिमांशु लिखती हैं-

किसी को प्रेयसी के माथे में चमकती लाल बिंदी सा लगता है बुरांश, किसी को कानों में लटकती बाली सा लगता है बुरांस कहीं अंधेरे में रोशन एक चिराग सा चमकता बुरांश,हाँ देखो,रंग भरने संवारने आसमान की चादर मुस्कुराते हुए खिल आया है बुरांश। अगली बार जब आप हिमालय की वादियों में समाए किसी राज्य में घूमने जाएं, तो बुरांश के फूलों की खूबसूरती और इसके जादुई गुणों का आनंद लेना न भूलें।

ममता गंगवाल कुशल नेतृत्व एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए 'सर्वश्रेष्ठ मंत्री' सम्मान से विभूषित

श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति मध्यांचल का अधिवेशन संपन्न

धार। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति मध्यांचल का अधिवेशन उज्जैन में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनिंद्र जैन, राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण लोनी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके सानिध्य में संपूर्ण मध्यांचल का अधिवेशन एवं अलंकरण समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में विगत तीन वर्षों के उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर संभाग स्तर पर विभिन्न सदस्यों को सम्मानित एवं अलंकृत किया गया। इस अवसर पर ममता गंगवाल को उनके कुशल नेतृत्व एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए 'सर्वश्रेष्ठ मंत्री' सम्मान से विभूषित किया गया।

ममता गंगवाल का आगामी सत्र हेतु वरिष्ठ कार्याध्यक्ष पद पर मनोनयन - साथ ही, राष्ट्रीय कार्यसमिति मंजू अजमेरा, ज्योति टोंग्या इंदु गांधी द्वारा ममता गंगवाल को आगामी सत्र हेतु वरिष्ठ कार्याध्यक्ष पद पर मनोनयन किया गया। धार संभाग से अध्यक्ष नीता झांझरी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सक्रिय सहभागिता की। इस अवसर पर धार संभाग को उत्कृष्ट कार्यों के लिए श्रेष्ठ संभाग एवं जीवदया सेवा का पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। जानकारी सचिव आशा बडजात्या ने दी।

आजादी के महान क्रांतिकारी मंगल पांडे को किया याद

बैतूल। भीमराव रामराव अंबेडकर शिक्षा महाविद्यालय बैतूल में 8 अप्रैल बुधवार को 1857 की क्रांति के महान सेनानी मंगल पांडे को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के संचालक इंजी. ध्रुवप्रकाश अग्रवाल और प्राचार्य डॉ. जीडी देशमुख ने मंगल पांडे की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया एवं उनके द्वारा किये गये कार्यों को याद किया गया। महाविद्यालय के सभागार में मंगल पांडे के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई एवं कार्यक्रम के अंत में मौन धारण किया। इस अवसर पर बीएड स्टाफ एवं बीएड स्कालर्स उपस्थित रहें।

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 10096 बालिकाओं का किया टीकाकरण

बैतूल। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 7 अप्रैल 2026 तक बैतूल जिले में कुल 10096 बालिकाओं को टीकाकरण किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बैतूल शहरी क्षेत्र में 387 बालिकाओं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभात पटटन में 865, आमला में 1302, घोड़ाडोगरी में 1592, सेहरा में 1276, चिचोली में 746, मुलताई में 913, आठनेर में 673, भैंसदेही में 706, शाहपुर में 615, भीमपुर 1021 इस प्रकार जिले में कुल 15217 के विरूद्ध 10096 कुल 66.3 प्रतिशत बालिकाओं को एचपीवी टीकाकरण किया गया। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी से होता है। एचपीवी टीका एक सुरक्षित और प्रभावी टीका है जो कैंसर से बचाने में मदद करता है। यह टीका जिला चिकित्सालय बैतूल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में निःशुल्क लगाया जा रहा है। समस्त अभिभावकों से अपील की है कि ऐसी बालिकाऐं जिनकी आयु 14 वर्ष तथा 15 वर्ष 3 माह तक की है वे अपनी बालिकाओं को एचपीवी टीकाकरण अवश्य करवाएं एवं बेटियों का भविष्य सुरक्षित बनाएं।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः राहत की बजाए आफत बने नए नियम, फार्म जमा करने लगाने पड़ रहे चक्कर

बीपीएल की अनिवार्यता और 200 जोड़ों की सीमा ने छीनी जोड़ों की उम्मीदें

एस. द्विवेदी बैतूल।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लागू किए गए नए नियम अब जरूरतमंद परिवारों के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। पहले यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत का जरिया मानी जाती थी, लेकिन अब बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता और जिले में केवल 800 जोडों के विवाह की सीमा ने कई परिवारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब केवल उन्हीं परिवारों की बेटियां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह हेतु पात्र होंगी, जिनके पास बीपीएल कार्ड होगा। इसके अलावा एक तिथि पर अधिकतम 200 जोड़ों का ही सामूहिक विवाह कराया जा सकेगा। सम्मेलन आयोजित करने के लिए कम से कम 11 जोड़ों का होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। पूर्व में इस योजना के लिए बीपीएल कार्ड की बाध्यता नहीं थी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, चाहे वे बीपीएल सूची में शामिल हों या नहीं, योजना का लाभ ले लेते थे। पांच जोड़ों के होने पर भी सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हो जाता था। लेकिन अब अधिकतम 200 और कम से कम 11 जोड़े की बाध्यता ने इस योजना का लाभ लेने वाले जरूरतमंद परिवारों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। हितग्राहियों का कहना है कि सरकार ने नए नियम तो बना दिए। परन्तु जमीनी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर दिया।

फार्म जमा करने परेशान हो रहे दूसरे विकासखंड के जोड़े - जनपद पंचायत बैतूल में 26 अप्रैल को होने जा रहे सामूहिक विवाह में 200 जोड़ों की सीमा तय है। इस विवाह में जनपद पंचायत बैतूल, जनपद पंचायत आठनेर और जनपद पंचायत आमला के अलावा नगर पालिका बैतूल, नगर परिषद बैतूलबाजार, नगर परिषद आठनेर और नगर पालिका आमला के 200 जोड़ों का विवाह होना है। ऐसे में तीन जनपद पंचायत और चार नगरीय निकाय से 200 जोड़े तय करना बड़ा मुश्किल होगा। जबकि एक जनपद पंचायत से ही जोड़ों की इतनी संख्या हो जाएगी। दूसरी तरफ विवाह में शामिल होने वाले जोड़ों को पहले संबंधित जनपद या नगर निकाय से सत्यापन कराने के बाद बैतूल में विवाह हेतु फार्म जमा करना पड़ रहा है। जिससे उन्हें बार-बार बैतूल के चक्कर काटने पड़ रहे है।

अधिक हुई संख्या, तो किस आधार पर होगा चयन, स्पष्ट नहीं - मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सीमा तय होने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस बात को लेकर भी चिंता है कि यदि निर्धारित जोड़ों से अधिक पंजीयन होते है, तो चयन किस आधार पर होगा। प्रशासन ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि अतिरिक्त आवेदन आने पर प्राथमिकता किसे दी जाएगी। हितगहियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि पंजीयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही, तो प्रभावशाली लोगों के परिचितों को पहले मौका मिल जाएगा और वास्तविक जरूरतमंद परिवार पीछे रह जाएंगे। लोगों ने मांग की है कि सरकार इस योजना के नियमों में संशोधन करे, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके।

बीपीएल सूची में नाम नहीं, तो नहीं मिलेगा योजना का लाभ- जिले में कई ऐसे परिवार हैं जो गरीबी में जीवनयापन कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका नाम बीपीएल सूची में नहीं है। ऐसे परिवारों की बेटियां अब योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। बताया जा रहा है कि कन्यादान योजना में इस बार कन्या और उसके अभिभावक का गरीबी रेखा में होना जरूरी है। बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन भी होना जरूरी है। पहले इस योजना में कोई भी वर्ग के लोग सम्मिलित होते थे, लेकिन इस बार केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ही इसका लाभ मिल सकेगा। ऐसे में जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, उन्हें इस योजना से वंचित रहना पड़ेगा।

2006 में शुरू हुई थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना - यहा उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने 2006 में निर्धन और जरूरतमंद परिवारों के कांधे से बेटियों का बोझ उतारने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान व निकाह योजना शुरू की थी। 20 साल में इस योजना में हजारों जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। लेकिन इस बार सरकार ने सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले जोड़ों के लिए नियमों में बदलाव और सीमा तय कर दी है। इससे कन्यादान योजना में विवाह करने का सपना सजोने वाले जोड़े असमंजस में हैं। विवाह योजना में पहले अपात्र लोग भी विवाह कर लेते थे, लेकिन इस बार प्रक्रिया कठिन कर दी है। ऐसे में जरूरतमंद परिवार पात्रता पूरी नहीं करने के कारण योजना से वंचित रह जाएंगे और उन्हें घर से बेटियों की शादी करनी पड़ेगी।

सीमा तय होने से बढ़ी परेशानी - शासन ने सामूहिक विवाह हेतु जोड़ों की संख्या तय कर दी है। 2025 तक इस योजना में जोड़ों की कोई सीमा तय नहीं की थी, लेकिन अब एक आयोजन में न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़े ही परिणय सूत्र में बंध पाएंगे। शासन की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अब जिले के 800 जोड़े ही परिणयबद्ध होकर योजना का लाभ ले सकेंगे। बताया जा रहा है कि बैतूल जिले में सिर्फ चार तिथियों पर ही कन्यादान योजना महोत्सव का आयोजन होगा। जिसमें 27 अप्रैल को पंचायत बैतूल, जनपद पंचायत आठनेर और जनपद पंचायत आमला के अलावा नगरपालिका बैतूल, नगर परिषद बैतूलबाजार, आठनेर और नगरपालिका आमला के कुल 200 जोड़े शामिल होगे।

इनका कहना है - इस बार कन्यादान योजना के लिए जोड़ों की सीमा तय कर दी गई है। जिले में चार जगहों पर होने वाले आयोजन में अधिकतम 800 जोड़े ही शामिल हो सकते है। एक जगह होने वाले कार्यक्रम में न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़े ही शामिल होगे। इसके अलावा बीपीएल पोर्टल पर कन्या और अभिभावक का सत्यापन होना भी जरूरी है।

- रोशनी वर्मा, उप संचालक, सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग बैतूल

आमला विकासखंड में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन कराने की मांग

● गरीब कन्याओं के साथ छलावा बनकर रह गई है योजना ● सेवादल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

बैतूल/आमला। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के नए नियमों को लेकर अब विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। जनपद पंचायत सभाकक्ष आमला में आयोजित जनसुनवाई के दौरान कांग्रेस सेवादल ने एसडीएम शैलेंद्र बड़ोनिया को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि योजना के नए नियम गरीब कन्याओं के लिए लाभ के बजाय छलावा साबित हो रहे हैं। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि सरकार ने विवाह के लिए जोड़ों की संख्या सीमित कर दी है, जो पूरी तरह गलत है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि संख्या की इस लिमिट को तत्काल खत्म किया जाए। जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं, उन सभी पात्र कन्याओं का विवाह सरकारी खर्च पर कराया जाना चाहिए ताकि कोई भी गरीब परिवार इस लाभ से वंचित न रहे। वर्तमान व्यवस्था के तहत आमला ब्लॉक के विवाह सम्मेलनों को बैतूल जनपद के साथ जोड़ दिया गया है। बैतूल में तीन ब्लॉकों के लिए मात्र 200 जोड़े का लक्ष्य रखा गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे आमला की कई बहनें योजना से बाहर हो जाएंगी। उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन या तो आमला नगर में या फिर जनपद की किसी भी ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाए।

राजेश सरियाम फिर बने मध्यप्रदेश प्रभारी

● ब्यूरो ने जताया भरोसा, दोबारा सौंपी जिम्मेदारी ● आदिवासी और गरीबों के लिए लगातार कर रहे काम ● नि:शुल्क कोचिंग और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका

बैतूल। राष्ट्रीय मानव अधिकार अपराध एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहित गुप्ता ने बैतूल जिले के युवा समाजसेवी राजेश सरियाम को एक बार फिर मध्य प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। उनकी पुनर्नियुक्ति से जिले में उत्साह का माहौल है और उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं।

राजेश सरियाम लंबे समय से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय रहकर सामाजिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लगातार आवाज उठाई है। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते हुए वे वर्षों से निशुल्क कोचिंग संस्थान संचालित कर रहे हैं, जिससे कई युवाओं को लाभ मिला है। सांस्कृतिक गतिविधियों में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। हाल ही में उन्होंने आदिवासी फोक स्टूडियो के माध्यम से आदिवासी युवक-युवतियों की कला को मंच प्रदान किया, जिससे उनकी प्रतिभा को प्रदेश और देश स्तर पर पहचान मिल रही है।

सरकारी नौकरी ठुकराकर चुना समाजसेवा का रास्ता - राजेश सरियाम ने सरकारी नौकरी को ठुकराकर समाजसेवा का मार्ग चुना और विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के लिए जमीनी स्तर पर काम किया। उनका मानना है कि आदिवासियों के नाम पर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन वास्तविक कार्य कम लोग करते हैं। उनकी सक्रियता, नेतृत्व क्षमता और समाज के प्रति समर्पण को देखते हुए ही संगठन ने उन्हें दोबारा यह जिम्मेदारी सौंपी है।

सीएमओ ने निर्माणाधीन गंज मंडी कॉम्प्लेक्स का किया निरीक्षण

पूर्ण हो चुकी दुकानों में व्यापारियों को शिफ्ट कराने एवं अतिक्रमण हटाने दिए निर्देश

बैतूल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के निर्देशानुसार बुधवार को नपा सीएमओ बैतूल नवनीत पाण्डेय ने गंज मंडी कॉम्प्लेक्स निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि कॉम्प्लेक्स में कुल 320 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर 142, मेजेनाइन फ्लोर पर 26, प्रथम तल पर 98 और द्वितीय तल पर 54 दुकानों का निर्माण किया जाना है। जी ब्लॉक में 66 और एफ ब्लॉक में 78 दुकानों का निर्माण कार्य जारी है। इस दौरान उन्होंने जी-2 ब्लॉक में 32 दुकानों के निर्माण के लिए साइट क्लियर करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए आसपास के अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण दल को कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएमओ श्री पाण्डेय ने मौके पर मौजूद अतिक्रमणकारियों से चर्चा कर उन्हें शीघ्र स्थल खाली करने के लिए कहा। साथ ही पूरी हो चुकी 44 दुकानों में व्यापारियों को जल्द शिफ्ट कराने के लिए राजस्व अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

झिरना धाम में बोरी बंधान साफ कर बढ़ाया जल संरक्षण, 5 फीट तक पानी सुरक्षित

मानव श्रृंखला बनाकर जल संरक्षण के प्रति जागरूकता की ली शपथ

बैतूल। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड भीमपुर द्वारा ग्राम पंचायत कुटंगा के ढढारी स्थित प्रसिद्ध शिव शक्ति धाम झिरना धाम में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बुधवार को व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जन अभियान परिषद द्वारा पूर्व में निर्मित बोरी बंधान के आसपास जमा गंदगी को हटाकर जल स्रोत को स्वच्छ एवं संरक्षित किया गया। यह अभियान जिला समन्वयक श्रीमती प्रिया चौधरी एवं ब्लॉक समन्वयक श्री राजू मांडवे के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। जिला समन्वयक प्रिया चौधरी ने बताया कि यह बोरी बंधान 28 दिसंबर 2025 को भीमपुर एवं चिचोली विकासखंड की संयुक्त जअप की टीम द्वारा लगभग 375 बोरियों से बनाया गया था। इसमें प्रस्फुटन समितियों, नवांकुर संस्थाओं तथा बैचलर ऑफ सोशल वर्क और मास्टर ऑफ सोशल वर्क के विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि इस बंधान का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल को रोककर जल संरक्षण को बढ़ावा देना है, जिससे न केवल ग्रामीणों बल्कि क्षेत्र के वन्य जीवों को भी जल उपलब्ध हो सके। वर्तमान में जब आसपास के अधिकांश नाले सूख चुके हैं, तब भी इस बंधान में अप्रैल माह में लगभग 4 से 5 फीट तक पानी संरक्षित है। यह पानी ग्रामीणों के मवेशियों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है, वहीं जंगल के जीव-जंतु भी इससे अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इसके साथ ही झिरना धाम धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थल है। महाशिवरात्रि और नवरात्रि जैसे पर्वों पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिन्हें इस जल स्रोत से काफी सुविधा मिलती है।

स्टॉप डेम बनने पर बढ़ेगा जल संचयन - पूर्व जनपद उपाध्यक्ष एवं जिला वन समिति अध्यक्ष मनोहरी परते ने बताया कि भविष्य में यहां स्थायी जल संरचना स्टॉप डेम बनाने के लिए डीएफओ से चर्चा की गई है, जिससे और अधिक जल संचयन किया जा सके।

महदगांव के प्राचीन तालाब पर जल स्रोत सेवा समागम कार्यक्रम का आयोजन

● ग्रामीणों ने श्रमदान कर की जल स्रोतों की साफ-सफाई, जल संरक्षण का लिया संकल्प

बैतूल। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष मोहन नगर के नेतृत्व में जिले में चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बैतूल विकासखंड के ग्राम महदगांव के प्राचीन तालाब पर द्वितीय चरण के जल स्रोत सेवा समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में तालाब का पूजन एवं श्रमदान कर जल संरक्षण का संकल्प लिया गया। जिला समन्वयक प्रिया चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर में विधि-विधान पूर्वक पूजा-अर्चना के साथ की गई। इसके पश्चात जल संरक्षण के नारों के साथ मंदिर प्रांगण से तालाब तक रैली निकाली गई। तत्पश्चात प्राचीन तालाब के समीप स्वच्छता अभियान चलाकर जल स्रोतों की साफ-सफाई की गई। इसके उपरांत आंगनवाड़ी केंद्र एवं माध्यमिक शाला महदगांव में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें ग्रामवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वच्छता एवं जल संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों एवं प्रतिभागियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इसमें यह संकल्प लिया गया कि भविष्य में भी जल स्रोतों की नियमित साफ-सफाई एवं संरक्षण कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई जाएगी। इस आयोजन के माध्यम से ग्राम के जल स्रोतों को स्वच्छ एवं संरक्षित रखने का भी संकल्प लिया गया तथा जल संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने का सराहनीय प्रयास किया गया।

16 से 30 अप्रैल तक खुलेगा स्व-गणना पोर्टल, 15-20 मिनट में पूरी होगी प्रक्रिया

बैतूल। जनगणना 2027 को अधिक आधुनिक, पारदर्शी एवं जन-सहभागी बनाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा स्व-गणना की अभिनव सुविधा प्रारंभ की है। जिला योजना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार गौतम ने बताया कि यह पहल नागरिकों को सशक्त बनाते हुए उन्हें स्वयं अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के मध्य राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चयनित 30 दिवस की अवधि में संपन्न की जाएगी। इसके पश्चात द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करते हुए इस बार डेटा संकलन के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। प्रगणकों द्वारा एचएलओ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से घर-घर जाकर जानकारी संकलित की जाएगी, वहीं आम नागरिकों के लिए स्व-गणना पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा। यह पोर्टल सर्वेक्षण प्रारंभ होने में 15 दिन पूर्व 16 अप्रैल से 30 अप्रैल आम जनता के लिए खुला रहेगा, जिसमें नागरिक सुविधानुमार अग्रिम रूप में अपनी जानकारी दर्ज कर सकें। स्व-गणना प्रक्रिया पूर्णतः सरल, सुरक्षित है।

कार्यालय नगरपालिका परिषद बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक/जल.शा./ई./1304 से 1309 बैतूल दिनांक 02/04/2026

// ई-टेन्डर आमंत्रण सूचना //

(प्रथम / द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना)

निम्नलिखित कार्य/सामग्री हेतु केन्द्रीकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/nicgep/app पर देखा जा सकता है।

क्र.	ऑन लाईन निविदा क्र.	कार्य / सामग्री का विवरण	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_496799_1 1st call	Supply of electrical materials related to water supply for Betul Municipal Council	1- 2026-27 2- 2500000/-	1- 5000/- 2-18800/-	06/05/2026
2	2026_UAD_496800_1 2nd call	Repairing of water supply motor pump and supply of maintenance releted material in Municipal council Betul	1- 2026-27 2- 1000000/-	1- 2000/- 2- 10000/-	21/04/2026
3	2026_UAD_496801_1 1st call	Supplying and providing Dg set and Genrator on rental basis 10kw, 20kw, 500 kva and 1000 kva for Betul Municipal Council	1- 2026-27 2- 500000/-	1- 2000/- 2- 5000/-	21/04/2026
4	2026_UAD_496802_1 1st call	Water samples testing work in Betul Municipal Council	1- 2026-27 2- 500000/-	1- 2000/- 2- 5000/-	21/04/2026
5	2026_UAD_496803_1 1st call	Providing supplying and fixing 240 Hp motor at Filter plant Betul	1- 2026-27 2- 2000000/-	1- 5000/- 2- 15000/-	06/05/2026
6	2026_UAD_496804_1 1st call	Providing supplying and fixing 335 Hp motor at Tapti Intake well Betul	1- 2026-27 2- 2500000/-	1- 5000/- 2- 18800/-	06/05/2026

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in/nicgep/app की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद बैतूल

संगीत, कला और साहित्य की त्रिवेणी है संकट मोचन संगीत समारोह

संकट मोचन संगीत समारोह-3

राजेन्द्र शर्मा

(लेखक संगीत समीक्षक और पूर्व शासकीय अधिकारी हैं)

संकट मोचन संगीत समारोह वाराणसी में अपने 103वें आयोजन में संगीत, कला और साहित्य की त्रिवेणी के रुप में स्थापित हो गया है। साल 1923 से 2013 तक विशुद्ध रूप से यह शास्त्रीय संगीत का समारोह था और इसके यहां तक आने की यात्रा भी कम दिलचस्प नहीं है। शुरुआती दौर में यह समारोह एक दिन का, उसके बाद तीन दिन, पांच दिन और अब यह आयोजन छह दिनों तक होता है । सातवें दशक तक इस समारोह में महिला कलाकारों को शामिल नहीं किया जाता लेकिन महंत पंडित वीरभद्र मिश्र ने 1976 से महिला कलाकारों के लिए समारोह के द्वार खोले। फिर मुस्लिम कलाकारों को भी आमंत्रित किया जाने लगा। बाद में महंत विशम्भर नाथ मिश्र को एक दिन ख्याल आया कि वाराणसी संगीत के अलावा ललित कलाओं के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है।

ख्यात पेंटर एम एफ हुसैन, राम कुमार, शंखो चौधरी, दिनेश प्रताप सिंह, लतिका कट्ट आदि ने बनारस में रहकर बनारस की घाटों पर अपनी कला उकेरी है, क्यों न संकट मोचन संगीत समारोह में कला वीथिका को भी जोड़ा जाए। इस की जिम्मेदारी उन्होनें अपने अनुज डॉ. विजय नाथ मिश्र को सौंपी। वर्ष 2014 से संगीत समारोह के साथ-साथ मंदिर परिसर में ही कला वीथिका का आयोजन भी किया जा रहा है। इस क्रम में कला वीथिका का यह बारहवां आयोजन है। इसमें बड़े कलाकारों से लेकर नवाकुंरों की कलाकृतियां एक साथ प्रदर्शित होती हैं। दर्शकों की माने तो यहां कला समीक्षकों, कलाकारों के अलावा आम सुधि दर्शक सीधे कलाकारों और उनकी कलाकृतियों से संवाद करने में समर्थ हो पाते हैं। इस वर्ष इस कला वीथिका में वाराणसी के राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम कर चुके पेंटर डॉ. सुनील विश्वकर्मा, अनिल शर्मा, प्रवीण पटेल, प्रो. उत्तमा दीक्षित, डॉ. संजय कुमार सिंह, राजीव लोचन साहू, डॉ. सुरेश चन्द्र जांगिड, मोहम्मद सुलेमान, मानसी शर्मा, रवि शंकर, अक्षत कुमार सिंह, पवन चौरसिया, जय गुता, आशीष राय, अंकित जायसवाल, मूर्तिकार राजेश कुमार, फोटोग्राफर मनीष खत्री के अलावा लखनऊ से डॉ. अवधेश मिश्रा, भूपेन्द्र अस्थाना, कलकत्ता से आलोक राय, बहरीन से सुभो सरकार जैसे प्रतिष्ठित कलाकारों की 600 से अधिक कृतियां दर्शकों को रिझा रही हैं।

कला वीथिका में मूर्तिकार राजेश कुमार ने शास्त्रीय संगीत की हस्तियों की लाइव मूर्तियां बनाकर एक नया आयाम स्थापित किया है। राजेश अब तक संतूर सम्राट पंडित शिव कुमार शर्मा, बांसुरी सम्राट पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, गायिका कंकना बनर्जी, राजेश्वर आचार्य, अनुप जलोटा,पंडित जसराज, गुंदेचा बंधु, रवीन्द्र जैन का गंगा की पावन मिट्टी से लाइव स्कल्प्चर बना चुके हैं।

संकट मोचन संगीत समारोह की कला वीथिका के संयोजक डॉ. विजय नाथ मिश्र ने कला वीथिका स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से लाइव कला प्रतियोगिता का आयोजित कर उन्हें पुरस्कृत करने का सिलसिला कायम किया । संकट मोचन संगीत समारोह में विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ के साथ-साथ हनुमान जी के अलग-अलग स्वरूपों को दिखाया जाता है। सुरों के प्रेमियों को इससे ज्यादा और क्या चाहिए ।

संकट मोचन संगीत समारोह के इस आयोजन में संगीत, कला के साथ साहित्य को भी जोड़ा गया है, जिससे यह आयोजन संगीत,कला और साहित्य की त्रिवेणी बन गया है। इसके लिए मंदिर परिसर में 'साहित्य मंच' स्थापित किया गया है । जिसमें 6 दिनों तक शाम को साहित्य चर्चाएं होंगीं। बीएचयू के आचार्य, कवि और आलोचक डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ला के निर्देशन में साहित्य मंच के पहले आयोजन में मालिनी अवस्थी की कृति 'चंदन किवाड', नागरी प्रचारिणी सभा के हाल ही में प्रकाशित पत्रिका 'नागरी',श्रीप्रकाश शुक्ल की पुस्तक 'भक्ति का लोकवृत' और रविदास की 'कविताई', प्रो. विजय नाथ मिश्र की पुस्तक 'दंडपाणि च भैरवं' पर समीक्षात्मक चर्चा के अलावा काशी में भक्ति तथा साहित्य और कला एक अंतः संबध विषयक चर्चा का आयोजन है । महंत विशम्भर नाथ मिश्र ने कहा कि संकट मोचन मंदिर प्रांगण गोस्वामी तुलसीदास की प्रयोगशाला है। उन्हें पहले ही दिन इस साहित्य मंच से भविष्य के लिटरेचर फैस्टिवल की झलक दिखाई दे रही है।

महावीरजी और अलवर में अद्वितीय नाटकों का मंचन

जैन रत्न साधना मादावत जैन रंगशाला इंदौर के निर्देशन में धर्मलाभ लिया

इंदौर। जैन रत्न साधना मादावत जैन रंगशाला इंदौर की ओर से महानाट्यमहामंचन श्री महावीर जन्म कल्याणक महामहोत्सव के पावन अवसर पर सांस्कृतिक संध्या के तहत रंगशाला प्रॉडक्शन की ओर से निर्देशिका जैन रत्न साधना मादावत जैन के निर्देशन में विगत दिनों लाइट साउंड राजस्थान के श्री

महावीर जी में नमोकार की शक्ति पर आधारित महानाट्य मंचन अमरकुमार चरित्र 'अमर आस्था' और बालक वर्धमान श्री महावीर के भव्य पालना उत्सव श्री महावीर जी की संपूर्ण कमेटी के साथ मनाया। जिसे दर्शकों की भरपूर सराहना मिली। रंगशाला प्रॉडक्शन इंदौर के 22 कलाकारों ने अमर कुमार के जीवन के मार्मिक पलों का जीवंत मंचन किया। जिसने दर्शकों के हृदय पर गहरी छाप छोड़ी। इस महागाथा के सफलतम मंचन ने निर्देशिका साधना मादावत जैन ने सांस्कृतिक माध्यम से धर्म प्रभावना का जो प्रतिसाद दिया, वह अति प्रशंसनीय है। जिसकी महिमा शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। महोत्सव के द्वितीय दिवस पर राजस्थान के अलवर नगर में भगवान महावीर के समावशरण की प्रथम आर्यिका' 'महासती चंदनबाला' की भक्ति पर आधारित भक्ति और वैराग्य की भव्यतम महानाट्य प्रस्तुति की गई। ये नाट्य मंचन श्री महावीर जी और अलवर नगर में श्री महावीर जन्म कल्याणक महामहोत्सव के पावन अवसर पर किए गए। जिसे श्रावक श्राविकाओं की बहुत सराहना मिल रही है। इसके लिए आपको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर कई सम्मान देश द्वारा दिए गए साथ ही 'द लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' सम्मानित किया। जैन रत्न साधना मादावत जैन द्वारा सांस्कृतिक माध्यम से धर्म प्रभावना का अप्रतिम कार्य देश भर में जैन कथाओं गाथाओं, चरित्रों पर आधारित महानाट्य मंचन का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। कलाकार हिमांशु प्रकाश, मयंक इलैशा हिमांकी, खुशबू खुशी सावन लाभम, भूमिका लविना आयुष्मान, जयशी मनस्वी लीना थे। प्रकाश व्यवस्था मनीष काला ने की। तकनीकी पक्ष आयुष अग्रवाल ने संपादित किया।

प्रमोद भार्गव को मिला सूरतगढ़ में लक्ष्मणराम सेवटा स्मृति कथा सम्मान

शिवपुरी। भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला एवं सामाजिक जागरण को समर्पित संस्था विविधा, सूरतगढ़ राजस्थान की ओर से प्रतिवर्ष दिए जाने वाले सम्मानों के अंतर्गत प्रमोद भार्गव को श्री लक्ष्मणराम सेवटा सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान साल 2024-25 के लिए उनके कथा संग्रह 'प्रमोद भार्गव की चुनिंदा कहानियां' पर दिया गया। प्रमोद को हाल ही में इसी कथा संग्रह पर महाराष्ट्र के नासिक में विद्योत्तमा सम्मान भी मिला है। इस अवसर पर शासकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में संस्कृत की प्राध्यापक डॉ श्रीमती हर्ष भारती ने कहानी संग्रह की गंभीर समीक्षा भी की।सम्मान समारोह राजस्थान के सूरतगढ़ में स्थित माहेश्वरी भवन में भव्य समारोह में संपन्न हुआ। प्रमोद भार्गव के अलावा कृष्णा

देवी कामरा स्मृति हिंदी कविता सम्मान डॉ प्रभा मुजुमदार (गुजरात) को उनके कविता संग्रह 'नकारती हूं निर्वासन' पर, राजस्थानी कविता के क्षेत्र में दिया जाने वाला श्रीमती गोपी देवी चांडक स्मृति सम्मान चांदकौर जोशी (जोधपुर)को उनके कविता संग्रह 'बिलखता बादल' को, जुगल किशोर सोमानी स्मृति व्यंग पुरस्कार वरिष्ठ व्यंगकार अखिलेश श्रीवास्तव (लखनऊ) को उनके व्यंग्य संग्रह 'दफ्तरनामा' पर,उपन्यास के क्षेत्र में भेरूदान सोमानी स्मृति उपन्यास पुरस्कार अलंकार रस्तोगी (लखनऊ) को उनके उपन्यास 'पंडित भया न कोई' तथा अर्जुन राम सुथार स्मृति प्रथम प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार डॉ नेहल शाह (भोपाल) को उनकी पहली कविता पुस्तक 'और इन सब के बीच' पर दिया गया। इसके अंतर्गत सभी लेखकों को 11,000 हजार की नकद राशि,स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र शॉल और श्रीफल भेंट किए गए। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉ एनके सोमानी और सचिव संजय कामरा ने चयनित साहित्यकारों को बधाई दी।

सांदीपनि विद्यालयों की हकीकत उजागर : 64 प्रतिशत तक छात्र फेल, शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल : जीतू पटवारी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बड़े-बड़े दावों के साथ शुरू किए गए 'सांदीपनि विद्यालय' आज अपनी बदहाली और गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता के कारण चर्चा में हैं। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार राजधानी भोपाल के एक सांदीपनि विद्यालय में 64 प्रतिशत तक विद्यार्थी फेल हो गए हैं। नौवीं कक्षा का परिणाम मात्र 48 प्रतिशत और 11वीं का 76 प्रतिशत रहा, जो सामान्य स्कूलों से भी खराब है। यह स्थिति बताती है कि सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित हैं।श्री पटवारी ने कहा कि सरकार लगातार स्कूलों के नाम बदलती रही–पहले मॉडल स्कूल, फिर सीएम राइज और अब सांदीपनि विद्यालय–लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये खर्च कर सुविधाओं और प्रशिक्षण की बातें की गईं, लेकिन जमीन पर परिणाम शून्य हैं।

राजस्व प्रकरणों का समयावधि में किया जाए निराकरण: कलेक्टर श्री विश्वकर्मा

टीएल बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने की सीएम हेल्पलाईन और शासकीय कार्यो की समीक्षा

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सीएम हेल्पलाईन, विभागीय गतिविधियों, समय सीमा वाले पत्रों, योजनाओं तथा अभियानों की साप्ताहिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सभी जिला अधिकारियों से कहा कि नवीन वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो गया है। सभी अभी से लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए कार्य करें।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी अधिकारी कार्यालय में समय से उपस्थित रहें तथा शासन की योजनाओं, सेवाओं और विकास कार्यो का लाभ आमजन तक सुगमता से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करें। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि राजस्व कोर्ट में प्रकरणों का समयावधि में निराकरण किया जाए। सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलम्ब हो। इसी प्रकार सभी तहसीलदारों को फार्मर रजिस्ट्री कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों से कहा कि जिले में

विभिन्न क्षेत्रों में फसल जलने की जानकारी प्राप्त हो रही है।अधिकारी इसमें संवेदनशीलता से काम करें तथा तत्काल मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाएं। साथ ही प्रकरण तैयार कराते हुए आरवीसी-64 के तहत मुआवजा उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देशित किया कि नरवाई जलाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही किसानों को समझाईश भी दी जाए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तैयारियों की जानकारी लेते हुए कहा कि आगामी 10 अप्रैल से उपार्जन शुरू हो रहा है। सभी एसडीएम तथा कृषि अधिकारी क्षेत्र में किसान संगठनों से चर्चा करें तथा तैयारियों का अवलोकन भी करें। राजस्व अधिकारियों को चना-मसूर उपज का सत्यापन पूर्ण कराने के लिए भी कहा। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के प्रकरणों तथा सिविल न्यायालय के प्रकरणों में जबावदावा दर्ज कराने के लिए भी निर्देशित किया। एचपीवी वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सीएमएचओ तथा बीएमओ को निर्देशित किया कि वैक्सीनेशन कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है, इसमें तेजी लाते हुए शीघ्र कार्य पूर्ण कराएं। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने रायसेन में 11 से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाले उन्नत कृषि मेला प्रदर्शनी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी तैयारियां शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जल संचय जनभागीदारी अभियान और जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यो की भी जानकारी लेते हुए एसडीएम तथा जनपद सीईओ को कार्यो का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की विभागवार और अधिकारीवार समीक्षा करते हुए जिला अधिकारियों को सीएम हेल्पलाईन का प्राथमिकता से संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराने के लिए निर्देशित किया। साथ ही नॉन अटेन्डेन्ट और निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी, अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर्स तथा जिला अधिकारी उपस्थित रहे। अनुभागों से एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ सहित अन्य अधिकारी वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

युवा संगम का आयोजन 13 को रोजगार और स्वरोजगार के सुनहरे अवसर एक ही मंच पर

विदिशा (निप्र)। जिले के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु 13 अप्रैल को 'युवा संगम' कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शासकीय आई.टी.आई. परिसर, जिला विदिशा में पूर्वाहन 11 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार मेला एवं अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित होकर युवाओं का साक्षात्कार लेंगे एवं योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगे। इसके साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सहित अन्य शासकीय विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी एवं ऋण सुविधा से संबंधित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है, जबकि आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच रखी गई है।

मोहनपुरा के प्रगतिशील कृषक ने पेश की मिसाल

नरवाई न जलाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में चलाए जा रहे नरवाई प्रबंधन अभियान के सकारात्मक परिणाम परलिक्षत हो रहें हैं। इसी क्रम में विकासखंड नटेरन की ग्राम पंचायत मोहनपुरा के कृषक श्री रामबाबू धाकड़ ने अपने खेत में नरवाई को जलाने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से उसका प्रबंधन कर एक सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री अजय प्रताप सिंह पटेल एवं प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री जगदीश गुर्जर की उपस्थिति में कृषक श्री धाकड़ द्वारा गेहूं की फसल कटाई के बाद शेष अवशेषों का उचित प्रबंधन किया गया। इस पहल से न केवल ग्राम पंचायत स्तर पर बल्कि पूरे जिले में उन्नत एवं पर्यावरण अनुकूल खेती का संदेश प्रसारित हुआ है। कृषक श्री धाकड़ ने बताया कि उन्हें यह प्रेरणा कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि रथ, विकसित कृषि

संकल्प अभियान तथा समय-समय पर आयोजित नरवाई प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रमों से मिली। उन्होंने नरवाई न जलाकर भूमि की उर्वरता बनाए रखने एवं प्रदूषण नियंत्रण में योगदान देने का कार्य किया है। उन्होंने क्षेत्र के अन्य कृषकों से भी अपील की है कि वे नरवाई को जलाने के बजाय सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, रोटावेटर एवं थ्रेशर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर वैज्ञानिक खेती अपनाएं। साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस प्रकार के नवाचारों को बढ़ावा दें, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ कृषि उत्पादन में भी वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनीं श्रीमती छायादेवी

अन्य महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा

विदिशा (निप्र)। शासन द्वारा युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर कई लोग सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं।

ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी गंजबासौदा की श्रीमती छायादेवी की है, जिन्होंने स्वरोजगार के माध्यम से न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, बल्कि क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए भी मिसाल प्रस्तुत की है। श्रीमती छायादेवी एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके मन में हमेशा कुछ नया करने और स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा थी। इसी दौरान उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, विदिशा के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके तहत स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया और उनका प्रस्ताव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बासौदा शाखा द्वारा स्वीकृत किया गया।

बैंक से उन्हें 25 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस वित्तीय सहयोग से उन्होंने 'परफेक्ट मार्केटिंग' नाम से बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स का व्यवसाय प्रारंभ किया। आज उनका व्यवसाय सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है और वे प्रतिमाह लगभग 85 हजार रुपये की स्थिर आय अर्जित कर रही हैं।

लोक सभा सांसद की अनुशंसा पर 03 निर्माण कार्य हेतु

नर्मदापुरम (निप्र)। सांसद लोकसभा श्री दर्शन सिंह चौधरी की अनुशंसा पर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा सांसद निधि से 03 निर्माण कार्य के लिए 02 लाख 49 हजार 118 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक सभा सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी की अनुशंसा पर नगर नर्मदापुरम के वार्ड नं 27 भीलपुरा वार्ड में शंकर मंदिर राजघाट के पास सार्वजनिक कवर्ड बैठक (टीन शेड) निर्माण के लिए 79 हजार 986 रूपये, नगर नर्मदापुरम के वार्ड क्रं 24 रसूलिया में सिंगाजी मंदिर के पीछे फुटपाथ निर्माण के लिए 99 हजार 169 रूपये तथा नगर नर्मदापुरम के वार्ड नं 26 रेवागंज वार्ड में खेडापति मंदिर के पास सार्वजनिक कवर्ड बैठक स्थल के लिए 69 हजार 963 रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

ग्राम मन्नूपुरा में आग लगने की घटना, प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले के ग्यारसपुर तहसील अंतर्गत ग्राम मन्नूपुरा तथा सियासी चक्र ग्राम में नरवाई में आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही प्रशासनिक अमला तत्परता के साथ मौके पर पहुंचा और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित विभागों द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जिससे संभावित नुकसान को सीमित किया जा सका। क्षेत्र के तहसीलदार श्री सौरभ वर्मा स्वयं मौके पर पटवारी एवं एईआरओ अधिकारियों के साथ उपस्थित रहे और स्थिति का जायजा लिया। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच की जा रही है। घटना के दौरान कोई भी किसान मौके पर उपस्थित नहीं मिला, जिससे नुकसान का तत्काल आकलन नहीं हो सका।

बिजली संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता से किया जाए समाधान : कलेक्टर

- ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से ही किया जाए खाद का वितरण, किसानों को न होना पड़े परेशान - कलेक्टर
- जल गंगा संवर्धन अभियान का किया जाए प्रभावी क्रियान्वयन - कलेक्टर
- नरवाई जलाने की घटनाओं पर सख्ती बरतने और जागरूकता बढ़ाने के कलेक्टर ने दिए निर्देश
- कलेक्टर की अध्यक्षता में टीएल बैठक आयोजित

एचपीवी टीकाकरण अभियान में लाई जाए तेजी - कलेक्टर

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में विभिन्न विभागों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से जुड़ी समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रशासन का पहला दायित्व जनता को समय पर राहत पहुंचाना है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली संबंधी समस्याओं के निराकरण में देरी के कारण लोगों को अनावश्यक परेशानी होती है और कई बार यह आक्रोश का कारण बनती है। अतः शिकायतों के समाधान में संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य किया जाए। संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी शेष प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदन आमजन की समस्या से जुड़ा होता है, इसलिए उन्हें गंभीरता से लेते हुए समय-सीमा में समाधान किया जाए। अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए एचपीवी टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने सीएचएमओ, डीईओ एवं डीपीसी को लक्षित वर्ग तक अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने, जागरूकता बढ़ाने और अभियान की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए, ताकि निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे किए जा सकें। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने नेशनल हाईवे एवं रेलवे परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि अर्जन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि भू-अर्जन की सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाएं, जिससे परियोजनाओं का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रभावित किसानों और भू-स्वामियों को समय पर उचित मुआवजा प्रदान किया जाए तथा किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी बाधा का तत्काल समाधान किया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में तेजी आने से जिले में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और आमजन को बेहतर आवागमन व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने खाद वितरण व्यवस्था को सुचारू एवं पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद का वितरण केवल ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से किया जाए, ताकि किसानों को लाइन में लगने या अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। वितरण केंद्रों पर छाया, पानी और बैठने जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने खाद दुकानों की नियमित जांच करने और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मप्र में महीने भर टली निगम-मंडलों में नियुक्तियां

अब जनभागीदारी, सहकारी समितियों में पहले एडजस्ट होंगे लोकल लीडर

भोपाल (नप्र)। एमपी में राजनीतिक पुर्नवास की आस लगाए बैठे भाजपा नेताओं का इंतजार लंबा होता जा रहा है। निगम-मंडल, बोर्ड और आयोगों में अब नियुक्तियां करीब एक महीने और टल गई हैं। अब संगठन का फोकस स्थानीय समितियों में लोकल लीडर्स के एडजस्टमेंट पर है।

5 राज्यों के चुनावों के बाद मिलेगा मंत्री का दर्जा

बीजेपी के सीनियर लीडर्स की मानें तो पार्टी का पूरा फोकस पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों पर है। जिन नेताओं को निगम मंडलों में एडजस्ट किया जा सकता है उनके नामों पर चर्चा हो चुकी है। कुछेक नामों को छोड़कर लगभग सभी नामों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। 4 मई को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद निगम-मंडलों में नियुक्तियों की लिस्ट घोषित होना शुरु हो जाएगी।

169 निकायों में एल्डरमैन हो चुके हैं नियुक्त- एमपी के नगरीय निकायों में एल्डरमैन नियुक्त किए जा रहे हैं। पहली लिस्ट में नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को मिलाकर 169 निकायों में एल्डरमैन नियुक्त किए जा चुके हैं। विश्वविद्यालयों की कार्यपरिषद में भी संघ, भाजपा और विद्यार्थी परिषद से जुड़े नेताओं को शामिल किया जा रहा है। अभी नगर निगमों सहित 244 निकायों में एल्डमैन नियुक्त होने हैं।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले : निगम-मंडल की नियुक्तियां छोटा विषय

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने निगम मंडलों को लेकर कहा- निगम मंडल की नियुक्तियां छोटा विषय है। 50-60 लोग ही निगम-मंडल में अध्यक्ष बनेंगे। अभी नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्तियां हो रहीं हैं। जनभागीदारी समितियां बना रहे हैं। हमारे मोर्चों में नियुक्तियां हो रहीं हैं नीचे की इकाईयां बन रहीं हैं। हजारों कार्यकर्ताओं और नागरिकों को शासन की समितियों और अन्य व्यवस्थाओं में पद देने का काम कर रहे हैं। निगम मंडल तो जब पार्टी चाहेगी तब घोषित हो जाएंगे।

सहकारिता मंत्री बोले

सहकारिता चुनावों पर रोक नहीं- भोपाल में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि अपेक्स बैंक सहित जिला सहकारी बैंकों में जल्द पदाधिकारी नियुक्त होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडल और अन्य समितियों में नियुक्तियां होंगी।मंत्री सारंग ने कहा कि सहकारिता के चुनावों पर कोई रोक नहीं हैं। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हमारी सरकार सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए कटिबद्ध है। जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे।

मध्यप्रदेश में लंबे समय बाद भूकंप की हलचल हुई

बड़वानी में कांपने लगी धरती, जमीन के 10किमी नीचे हलचल, घरों के बाहर भागे लोग

भोपाल/बड़वानी (नप्र)। जिले के अंजड़ और सेंधवा क्षेत्र में बुधवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया। दोपहर करीब 12:48 बजे अचानक धरती में कंपन महसूस हुआ। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी तीव्रता लगभग 3.6 दर्ज की गई, जबकि कुछ स्थानों पर 3.4 रिक्टर स्केल मापी गई है।

सेंधवा के सुदामा कॉलोनी निवासी ऑटो पार्ट्स व्यापारी रत्नेश जैन और उनकी पत्नी मोनिका जैन ने बताया कि वे घर में दीवार के सहारे बैठे थे, तभी अचानक कंपन महसूस हुआ। वहीं, व्यवसायी गिरीश गोयल ने तेज आवाज सुनने की भी जानकारी दी।

दो मिनट तक महसूस हुए झटके- अंजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम मोहिपुरा में भी झटके स्पष्ट रूप से महसूस किए गए। ग्रामीणों के अनुसार कंपन करीब 1 से 2 मिनट तक महसूस हुआ। झटके लगते ही लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। गांव के लोकेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि वे दोपहर में सो रहे थे, तभी अचानक तेज झटका लगा, जिसके बाद वे तुरंत बाहर आए और अन्य लोगों से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस तरह का अनुभव पहली बार हुआ है। सोहन कनास, एडीएम,बड़वानी ने कहा कि जिले के सेंधवा क्षेत्र में कपंन महसूस किया गया है। भूकंप के हल्के छटके लगे हैं। दोपहर में कुछ समय के लिए हलचल हुई है। हालांकि नुकसान की कोई खबर नहीं है

घरों के बर्तन, फर्नीचर हिलने लगा

ग्रामीणों ने घरों में रखे बर्तन, पंखे और फर्नीचर को हिलते हुए देखा। इंदिरा सागर पावर स्टेशन की भूकंप वेधशाला और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की वेबसाइट पर भी इस भूकंप की पुष्टि हुई है। जिला मुख्यालय स्थित भूकंप केंद्र में लगी सिस्मोमीटर मशीन में भी 3.4 रिक्टर स्केल की तीव्रता दर्ज की गई। भूकंप केंद्र के ऑपरेटर हुकुम कुमार ने बताया कि एमईक्यू (माइक्रो अर्थक्विक) मशीन 24 घंटे संचालित होती है और 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में हलचल दर्ज करती है। वहीं, बड़वानी की प्रभारी एडीएम सोहन कनास ने सेंधवा क्षेत्र से कंपन की सूचना मिलने की पुष्टि की है। फिलहाल किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।

छठवीं क्लास के छात्र से प्रिंसिपल ने झलवाया पंखा

रीवा में ईयरफोन लगाकर गाने सुनती रहीं; कलेक्टर ने डीईओ को फटकारा, जांच सौंपी

रीवा (नप्र)। रीवा के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के छात्र से पंखा झलवाते वीडियो सामने आया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) रामराज मिश्रा को फटकार लगाई। जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। मामला त्योंथर में शासकीय माध्यमिक शाला पनासी में मंगलवार का है। इसका वीडियो बुधवार को सामने आया। इसमें प्रिंसिपल वर्षा मांझी कुर्सी पर बैठी हैं। उनके कानों में ईयरफोन लगे हैं। पास ही खड़ा छठवीं क्लास का छात्र हाथ में पंखा पकड़कर हवा कर रहा है।

तीन सदस्यीय कमेटी कर रही जांच

डीईओ रामराज मिश्रा ने कहा- जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है। जो स्कूल जाकर छात्रों से बातचीत करेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।वहीं, छात्र के परिजन का कहना है कि वे गरीब और पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए ऐसे मामलों से डरते हैं। बच्चों का भविष्य खराब न हो, इस कारण उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। हालांकि उनका कहना है कि स्कूल में इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है।

प्रदेश में पिछले दो सालों में रेल सेवाओं में हुआ अभूतपूर्व विस्तार

रेलवे ट्रैक का विस्तार बढ़कर हुआ 5200 किमी

- देश का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क
- डबल इंजन सरकार का एक आदर्श मॉडल बनकर उभरा मध्यप्रदेश

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अथक प्रयासों के फलस्वरूप मध्यप्रदेश में पिछले दो सालों में रेल सेवाओं और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। मध्यप्रदेश 'डबल इंजन सरकार' का एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। अब प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और रेल कनेक्टिविटी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाले शीर्ष दस राज्यों में से एक है। रेलवे ट्रैक की लंबाई बढ़कर 5,200 किलोमीटर हो गई है, जो देश के कुल रेल नेटवर्क का 7.6 प्रतिशत है। बेहतर रेल सेवाओं के माध्यम से देश के सभी हिस्सों तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। मध्यप्रदेश के लिए आवंटित रेलवे बजट में 24 गुना वृद्धि हुई है। इस वर्ष 15,188 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष यह राशि 14,745 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2009 से 2014 तक, वार्षिक बजट केवल 632 करोड़ रुपये था। वर्तमान में 1,18,379 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न रेल परियोजनाएँ अलग-अलग चरणों में चल रही हैं।

आर्थिक विकास में आयेगी तेजी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों से केंद्र सरकार ने कई प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे राज्य को आर्थिक परिवर्तन की गति तेज करने में मदद मिली है। इस प्रगति का श्रेय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच गहरी आपसी समझ और समन्वय को जाता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जबलपुर-गोंदिया रेलवे लाइन और इंदौर-मनमाड रेलवे लाइन के दोहरीकरण, तथा सिंहस्थ कुंभ मेलाः 2028 के संदर्भ में अन्य अधोसंरचना विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बड़ी उपलब्धि यह है कि राज्य में रेल लाइनों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना में छह स्टेशनों - कटनी दक्षिण, नर्मदापुरम, ओरछा, सिवनी, शाजापुर और श्रीधाम - पर पुनर्विकास का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा, पूरे राज्य में 74 स्टेशनों को अपग्रेड किया जा रहा है। यात्रियों के लिये 3,163 करोड़ रुपये की आधुनिक सुविधाएँ विकसित की जा रही है। वंदे भारत ट्रेनें यात्रियों के लिए वरदान साबित हुई हैं। इनमें भोपाल-नई दिल्ली, इंदौर-नागपुर, भोपाल-रीवा और खजुराहो-बनारस शामिल हैं। इंदौर और भोपाल में 2 मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, जिनसे शहरी आबादी को राहत मिली है। रायसेन ज़िले के उमरिया गाँव में 1800 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण इकाई बनाई जा रही है। इससे 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

बड़े राज्यों में सीधा संपर्क

जबलपुर-गोंदिया रेल लाइन के दोहरीकरण से महाकौशल क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। इससे पर्यटन, धार्मिक गतिविधियों और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में 5,200 करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश किया गया है। कान्हा नेशनल पार्क और धुआँधार जलप्रपात जैसे पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।

पति की हत्या के बाद रोती रही पत्नी, लूट का ड्रामा

धार में बॉयफ्रेंड के लिए दी 1 लाख की सुपारी

धार (नप्र)। धार जिले के गोंदीखेड़ा चारण गांव में सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात एक ऐसा हत्याकांड हुआ, जिसने सबको झकझोर दिया। जिस पत्नी ने रो-रोकर पुलिस को लूट और बंधक बनाने की आपबीती सुनाई थी, वह खुद अपने पति की कातिल निकली।पुलिस ने महज 6 घंटे की जांच में उस पत्नी का नकाब उतार दिया, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात की पटकथा लिखी थी। जांच में सामने आया कि प्रियंका पुरोहित (27) ने अपने पति देवकृष्ण पुरोहित को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी कमलेश (33) के साथ साजिश रची। इस साजिश के तहत कमलेश ने अपने साथी सुरेंद्र पिता प्रताप सिंह को करीब 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी और पूरी घटना को लूट का रूप देने की पहले से प्लानिंग की गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सुपारी लेने वाला आरोपी सुरेंद्र फरार है।

इंदौर के राजा रघुवंशी कांड जैसा मामला

धार पुलिस के मुताबिक, यह मामला ठीक वैसा ही है, जैसा इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में हुआ था। वहां भी पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाया था। गोंदीखेड़ा में भी प्रियंका ने अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर पति देवकृष्ण की हत्या को लूट का रंग देने की कोशिश की। दराज से सोने-चांदी के गहने गायब बताए गए थे। हालांकि पुलिस जांच में सामने आया कि कथित लूट का सामान घर में ही छिपाकर रखा गया था, जिससे पूरी कहानी पर शक और गहरा गया।

मनगढ़ंत कहानी बताई : बदमाशों ने हाथ-पैर बांधे और लूट ले गए- वारदात के बाद प्रियंका ने पुलिस को बताया कि रात में अज्ञात बदमाश घर में घुसे और उन दोनों को अलग-अलग कमरों में बंधक बना लिया।

उक्त घटना को संवेदनशीलता व गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर ग्रामीण जोन इन्दौर अनुराग (भा.पु.से.), उपमहानिरीक्षक इन्दौर ग्रामीण जोन इन्दौर मनोज कुमार सिंह (भा.पु.से.)., उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक धार मयंक अवस्थी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार पारुल बेलापुरकर के नेतृत्व में एसडीओपी सरदापुर विश्वदीपसिंह परिहार के मार्गदर्शन में विशेष टीमें गठित की गई।

पुलिस को ऐसे हुआ शक?

एसपी मयंक अवस्थी के नेतृत्व में जब जांच शुरू हुई तो प्रियंका के बयानों में विरोधाभास नजर आया।

सिर पर 12 इंच गहरा घाव: हमला इतना सटीक और वीभत्स था कि यह सामान्य लूट नहीं, बल्कि रंजिश लग रही थी।

संदेहास्पद आचरण: प्रियंका के बयानों में बार-बार बदलाव और मोबाइल का गायब होना पुलिस को खटक गया।

घटनास्थल के साक्ष्य: सूत्रों के मुताबिक, घटनास्थल से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे आशंका जताई जा रही है कि कत्ल के बाद आरोपी प्रेमी और प्रेमिका के बीच शारीरिक संबंध भी बने थे।

सख्ती के आगे टूटा कातिल पत्नी का सब्र- देर रात जब पुलिस ने प्रियंका से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कुबूल कर लिया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी राजोद निरीक्षक रामसिंह राठौर, थाना प्रभारी तिरला निरीक्षक ज्योति पटेल, थाना प्रभारी सरदारपुर निरी.अनिल जाधव, थाना प्रभारी राजगढ निरी. समीर पाटीदार, थाना प्रभारी अमझेरा निरीक्षक राजू मकवाना, उनि हिना जोशी, चौकी प्रभारी रिंगनोद उनि गुलाब भयडिया, सउनि पीएस डामोर, सउनि सुनिल राजपूत, सउनि रमेशचन्द्र भाभर, प्र.आर. अर्जुनसिंह, प्रआर. विपिन कटारा, आर. दिलिप, आर. अंकित रघुवंशी, आर. महेन्द्र, आर. विक्रम अहिरवार, आर.लालसिंह, आर.वेलसिंह, आर.राकेश, आर.करण, म.आर. रमिला पचाया व सायबर सेल प्रभारी उ.नि. प्रशांत गुंजाल, सायबर सेल धार टीम के प्रआर. सर्वेशसिंह सोलंकी, प्रआर बलराम भंवर, आर.प्रशांत सिंह चौहान, आर. रोहित नरगावे, आर. मनीष पाल, आर शुभम शर्मा का योगदान रहा ।

रानी कमलापति स्टेशन के बाहर एक्टर से लूट

मुंबई से लौटे थे, फोन पर बात कर रहे थे, बाइक सवार झपट ले गए मोबाइल

भोपाल (नप्र)। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाहर मंगलवार को एक्टर राहुल चेलानी के साथ मोबाइल स्नैचिंग की वारदात हुई। जानकारी के मुताबिक, राहुल मुंबई से भोपाल लौटे थे और नर्मदापुरम जाने के लिए स्टेशन के बाहर कैब बुक करने निकले थे। इसी दौरान वे फोन पर बात कर रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाश आए और उनका मोबाइल झपटकर फरार हो गए।घटना के बाद राहुल ने हबीबगंज थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। नर्मदापुरम निवासी राहुल चेलानी कई टीवी शो और फिल्मों में काम कर चुके हैं। वे शूटिंग के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं और अक्सर भोपाल-नर्मदापुरम आते-जाते रहते हैं।

नोटबंदी के दौरान आए थे सुर्खियों में

राहुल चेलानी इससे पहले नोटबंदी के दौरान भी चर्चा में रहे थे। होशंगाबाद में पुलिस ने उनके पास से 43 लाख 60 हजार रुपए की नई करेंसी बरामद की थी। उस समय उन्होंने दावा किया था कि यह रकम उनकी मेहनत की कमाई है, जिसके बाद मामला आयकर विभाग को सौंपा गया था।

कॉलेज छात्रा से पड़ोसी ने रेप किया

- हत्या की धमकी देकर चार सालों से बना रहा था संबंध

भोपाल (नप्र)। मिसरोद इलाके में कॉलेज छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। कालोनी में रहने वाला युवक उसके साथ बीते चार सालों से लगातार संबंध बना रहा था। हत्या की धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया गया है। मंगलवार की रात थाने पहुंची पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

एसआई श्वेता शर्मा के मुताबिक मिसरोद में रहने वाली 19 साल की युवती कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। पीड़िता छात्रा ने पुलिस को बताया कि 2022 में जब वह नाबालिग थी, तभी उसके कॉलोनी में रहने वाला दीपक यादव उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। जहां उसने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी युवक कैटरिंग का काम करता है।

पाँचों बिजली कम्पनी स्वीकृत पदों में भर्ती प्रक्रिया शीघ्र करें : ऊर्जा मंत्री

विभागीय योजनाओं की गहन समीक्षा

भोपाल(नप्र)। पाँचों बिजली कम्पनी स्वीकृत पदों में भर्ती प्रक्रिया शीघ्र करें। हर हाल में अगले महीने तक भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी हो जाना चाहिए। 132 केव्ही के स्वीकृत सभी सब स्टेशन का कार्य जल्द पूरा करेगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश बुधवार को मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा में दिए। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि मेंटिनेंस और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किये गए कार्यों के बाद भी ट्रिपिंग क्यों हो रही है। इसका स्थाई निदान ढूंढे। उन्होंने कहा कि पायलेट प्राजेक्ट के रूप में एक फीडर लें और उसमें सभी संभावित उपाय कर यह सुनिश्चित करें कि उसमें कोई ट्रिपिंग नहीं हों। यह प्रयोग सफल होने पर अन्य फीडरों में भी इसे लागू किया जाए। बिजली का बिल समय पर नहीं पहुँचने और कार्यवाही तब करने जब बिल बढ़ जाता है, की स्थिति उचित नहीं है। बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्तों के विरूद्ध पहले या दूसरे महीनें में ही कार्यवाही करे। इससे वह बिल का भुगतान कर सकेगा।

अच्छा परफार्मेंस नहीं देने वाले सीई और एसई के खिलाफ करें कार्यवाही- ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि जो सीई और एसई अच्छा परफार्मेंस नहीं दे रहे है, उनके विरूद्ध कार्यवाही करें। मेंटिनेंस कार्यों के सतत् मॉनिटरिंग इनके माध्यम से करवायें।

गलत एवं फाल्स बिलिंग को सुधारने बनायें कार्ययोजना

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि गलत एवं फाल्स बिल की गहन जांच हो। साथ ही इनका निराकरण समय-सीमा में होना चाहिए। इसके लिये जरूरी हो तो अधिकारों का विकेन्द्रीकरण भी करे। वितरण केन्द्र एवं संभाग स्तर पर जनसुनवाई शिविर लगाएं जाएं।

वसूली और उपभोक्ता संतुष्टि वर्ष के रूप में मनाएं- मंत्री श्री तोमर ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष को वसूली और उपभोक्ता संतुष्टि वर्ष के रूप में मनाएं। इसके लिये सुनियोजित कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करें। उन्होंने कहा कि वे खुद भी ऐसे अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। वसूली के कार्यों में स्टॉफ की कमी हो तो सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियो की सेवाएं भी लेने का प्रस्ताव बनाएं। बिजली कंपनियों के भवनों में विज्ञापन के लिये स्पेस देकर आय बढ़ाने के प्रयास करें। समाधान योजना में लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें। बड़े बकायदारों से पहले वसूली करें।

सिंहस्थ: 2028 के कार्य प्राथमिकता से करें- सिंहस्थ:2028 से संबंधित सभी कार्य तय समय-सीमा में करें। कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। इन कार्यों की सतत् समीक्षा करें। सिंहस्थ संबंधित ट्रांसमिशन कम्पनी के कार्यों की बिन्दुवार समीक्षा की गई। मंत्री श्री तोमर ने मिशन कम्पनी के कार्मिकों को इनसेंटिव देने की बात भी कही।